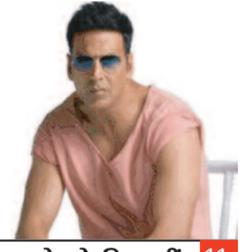




राहुल गांधी एक 12 अबोध बालक, वे...

# राष्ट्रीय शिखर

खबरों की स्वतंत्रता



इमेज के लिए नहीं करता देशभक्ति... 11

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र गौतमबुद्धनगर, नई दिल्ली, देहरादून और लखनऊ से एक साथ प्रसारित

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

वर्ष - 01, अंक - 351

गाजियाबाद / बुधवार 25 मार्च 2026

PRGI No. - UPHIN/25/A0086

पृष्ठ-12, मूल्य - 04 रूपए

## अमेरिका और इजराइल ने ईरान में दो गैस संयंत्रों और एक पाइपलाइन पर किया हमला

### ● खोरमशहर के गवर्नर ने किया दावा

तेहरान (एजेंसी)। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि मंगलवार को अमेरिका और इजराइल ने दो गैस संयंत्रों और एक पाइपलाइन को निशाना बनाया गया। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला न करने की टिप्पणी के बाद किया गया।



को रिपोर्ट करने वाला फार्स ईरान का अकेला न्यूज आउटलेट है। इसने कहा कि एक हमले में देश के दक्षिण-पश्चिम में खोरमशहर पावर प्लांट की गैस पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया। फार्स ने इराक की सीमा से लगे शहर के गवर्नर के हवाले से बताया कि खोरमशहर गैस पाइपलाइन प्रोसेसिंग स्टेशन के बाहर के इलाके में एक प्रोजेक्टवाइल गिरा। गवर्नर के हवाले से बताया कि ईरान के खोरमशहर पावर प्लांट

की गैस पाइपलाइन को निशाना बनाकर किए गए हमले से प्लांट के ऑपरेशन में कोई रुकावट नहीं आई और न ही कोई नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दृष्ट पोस्ट में दावा किया कि उनके लोग मिडिल ईस्ट तनाव कम करने के लिए प्रयासरत हैं। ईरान के साथ सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत जारी है। इसी को देखते हुए उन्होंने पांच दिनों तक ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले न करने का निर्देश दिया है। हालांकि इसके बाद ईरान का जवाब आया। ईरान ने कहा है कि वह मौजूदा संघर्ष में पीछे हटने वाला नहीं है। स्पष्ट कहा कि जब तक उसे हुए नुकसान की भरपाई नहीं होती, तब तक जंग जारी रहेगी।

## कुछ किसानों की आय तो तीन से आठ गुना तक बढ़ी: शिवराज

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंगलवार को केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि देश में कई किसानों की आय दोगुनी ही नहीं, बल्कि यह कई गुना तक बढ़ी है। वे किसानों की आय दोगुनी करने के मुद्दे पर बोल रहे थे। चौहान ने कहा कि किसानों की आय सिर्फ दोगुनी ही नहीं हुई है बल्कि इसमें दो-तीन गुना तक इजाफा हुआ है और कुछ मामलों में यह आठ गुना तक बढ़ा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों के समय गांवों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी। उन्होंने कहा कि उस समय न बिजली थी, न पानी और न ही सड़कें थीं। मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि पहले वहां किसानों को सिर्फ एक ही फसल मिल पाती थी,



बढ़ोतरी हुई है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पहले कृषि बजट 19,306 करोड़ रूपए था, जिसे बढ़ाकर अब 1 लाख 30 हजार करोड़ रूपए से अधिक कर दिया गया है। अगर कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों को मिलाकर देखा जाए तो कुल बजट 5 लाख करोड़ रूपए से भी ज्यादा हो गया है। उत्पादन के आंकड़ों पर बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले जहां उत्पादन 14 प्रतिशत के आसपास था, अब इसे बढ़ाकर 44 प्रतिशत तक पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रूपए की सहायता 'निधि सम्मान' के रूप में दे रही है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिए किसानों को आसानी से लोन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

क्योंकि बिजली की स्थिति बेहद खराब थी। उन्होंने कहा कि बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। कई बार तो सिर्फ बिजली के बिल ही आते थे। उन्होंने बताया कि सरकार ने सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई। इसका परिणाम यह हुआ कि आज मध्य प्रदेश में किसान साल में तीन-तीन फसलों ले रहे हैं, जिससे उनकी आय में

## नीतीश कुमार निर्विरोध जदयू अध्यक्ष निर्वाचित

पटना (एजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को एक बार फिर निर्विरोध रूप से जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। नामांकन के वापस लिए जाने के अंतिम समय गुजर जाने के बाद उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। नीतीश कुमार के अलावा किसी और नेता ने अपना पत्रा दाखिल नहीं किया। जदयू के राष्ट्रीय सचिव और मुख्यालय प्रभारी मोहम्मद निसार ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

## अब समय के हिसाब से तय होगा रेल टिकट कैंसिलेशन का रिफंड

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय रेलवे ने कन्फर्म टिकट कैंसिल करने के नियमों में बदलाव किया है ताकि दलालों द्वारा टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। नए नियमों के तहत यात्रियों को कुछ मामलों में ज्यादा सुविधा भी दी गई है, खासकर आखिरी समय में बोर्डिंग स्टेशन बदलने को लेकर। संशोधित नियमों के अनुसार, टिकट कैंसिल करने पर मिलने वाला रिफंड अब ट्रेन के चलने से पहले बचे समय के आधार पर तय होगा। साथ ही, यात्रियों को बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा भी दी गई है, जिससे उन्हें अधिक लचीलापन मिलेगा। ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। नए नियमों के तहत अगर कोई यात्री ट्रेन के चलने से 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करता है, तो उसे अधिकतम रिफंड मिलेगा और सिर्फ एक तय कैंसिलेशन चार्ज ही काटा जाएगा। अगर टिकट 72 घंटे से 24 घंटे के बीच कैंसिल किया जाता है तो किराए का 25 प्रतिशत काटा जाएगा (न्यूनतम चार्ज के साथ)। अगर टिकट 24 घंटे से 8 घंटे पहले कैंसिल किया जाता है, तो 50 प्रतिशत किराया काटा जाएगा। वहीं, अगर ट्रेन के चलने से 8 घंटे से कम समय पहले टिकट कैंसिल किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कुछ दलाल पहले ज्यादा टिकट बुक कर लेते थे और जो टिकट नहीं बिकते थे, उन्हें ट्रेन के समय से पहले कैंसिल कर देते थे, जिससे उन्हें ज्यादा पैसा वापस मिल जाता था। नए नियम इस तरह की गतिविधियों को रोकने में मदद करेंगे। इसके अलावा, रेलवे ने यात्रियों को यह सुविधा भी दी है कि वे ट्रेन के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। इससे खासकर बड़े शहरों में रहने वाले यात्रियों को फायदा होगा, जहां एक से ज्यादा रेलवे स्टेशन होते हैं। फिलहाल, बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा चार्ट बनने से पहले तक ही मिलती है, लेकिन नए नियम के बाद यात्रियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी।

## ट्रंप ने पाक सेना प्रमुख मुनीर से फोन पर की बात



वॉशिंगटन (एजेंसी)। ईरान से युद्ध में फंसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनीर से फोन पर बात की। सूत्रों के अनुसार, बातचीत में पाकिस्तान ने खुद को अमेरिकी और ईरानी वरिष्ठ अधिकारियों के बीच वार्ता की संभावित जगह के रूप में पेश किया। हालांकि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिवित् ने कहा कि ये संवेदनशील कूटनीतिक चर्चा है और अमेरिका मीडिया के जरिए कोई वार्ता नहीं करेगा।

## अमेरिका-इजराइल की ईरान से जंग से बन रहे भयावह हालात, पूरी दुनिया परेशान आने वाला समय देश की अग्निपरीक्षा: मोदी

- राज्यों की सरकारों से मांगा सहयोग
- टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करने की अपील

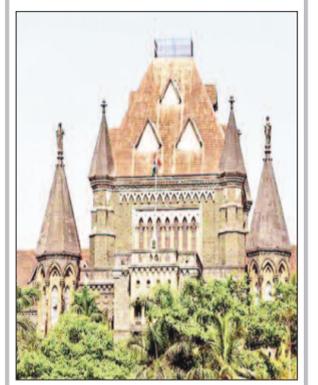


नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात को लेकर देशवासियों को आगाह किया। राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका-इजराइल की ईरान से जंग अगर जारी रही तो इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि

आने वाला समय देश की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। इसमें राज्यों का सहयोग जरूरी है। टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इस युद्ध ने पूरी दुनिया में बड़ा ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है, जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा है।

भारत पश्चिम एशिया के सभी प्रमुख देशों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्षेत्र के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर दो दौर की बातचीत की है और ईरान, इजरायल और अमेरिका के साथ भी निरंतर संवाद जारी है। भारत ने इस समस्या के समाधान के लिए संवाद का ही रास्ता सुझाया है। पीएम मोदी ने बताया कि स्टेट ऑफ होर्मुज में बड़ी संख्या में जहाज फंसे हुए हैं, जिनमें भारतीय क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में इस तरह की रुकावट और

## दिशा सालियान केस की अंतिम रिपोर्ट 24 घंटे में पेश करें



मुंबई (एजेंसी)। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर तेजी से सुर्खियों में आ गया है। इस बार बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतिम जांच रिपोर्ट में देरी को लेकर सरकार और जांच एजेंसियों पर नाराजगी जताई है। अदालत ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जांच एजेंसी 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करे।

कोर्ट ने कहा कि आखिर फाइनल रिपोर्ट अब तक क्यों जमा नहीं की गई। सुनवाई के दौरान जब सरकारी पक्ष ने नए सबूतों की जांच का हवाला देते हुए समय मांगा, तो कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह से जांच को अनिश्चित समय तक टाला जाता रहेगा? इस मामले में दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपनी याचिका में मांग की है कि उनकी बेटी की मौत को आत्महत्या न मानते हुए हत्या का मामला दर्ज किया जाए। उनका कहना है कि अब तक की जांच में कई अहम पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है और सच्चाई सामने लाने के लिए नए सिरे से जांच जरूरी है। कोर्ट में चल रही इस सुनवाई ने एक बार फिर इस पूरे मामले को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

## दूसरा धर्म अपनाने पर एससी दर्जा नहीं मिलेगा: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित है और वह हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। यह फैसला जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारीया की पीठ ने सुनाया। अदालत ने कहा कि अनुसूचित जाति का दर्जा भारतीय संविधान के तहत केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों तक सीमित है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपनाता है और उसका सक्रिय रूप से पालन करता है तो वह एससी श्रेणी के अनुसार, प्लेटफॉर्म फीस में करीब 17 प्रतिशत या 2 रूपए 59 पैसे का इजाफा हुआ है। इससे पहले स्वामी ने अगस्त 2025 में स्वामी ने प्लेटफॉर्म फीस में करीब 2 रूपए की वृद्धि की थी, जो कि पहले 12 रूपए थी।



ईसाई धर्म अपना लेते हैं, वे अपनी अनुसूचित जाति की पहचान बनाए नहीं रख सकते और ने कहा कि अनुसूचित जाति का दर्जा भारतीय संविधान के तहत केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों तक सीमित है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपनाता है और उसका सक्रिय रूप से पालन करता है तो वह एससी श्रेणी के अनुसार, प्लेटफॉर्म फीस में करीब 17 प्रतिशत या 2 रूपए 59 पैसे का इजाफा हुआ है। इससे पहले स्वामी ने अगस्त 2025 में स्वामी ने प्लेटफॉर्म फीस में करीब 2 रूपए की वृद्धि की थी, जो कि पहले 12 रूपए थी।

## ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से छोटे बच्चों के ई-व्हीकल चलाने पर लगेगा प्रतिबंध

बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर लिया फैसला सिडनी (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य में नए सुरक्षा कानूनों के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवाइस यानि ई-व्हीकल (जैसे ई-बाइक और ई-स्कूटर) चलाने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला मंगलवार को घोषित किया गया। राज्य सरकार ने बताया कि ई-मोबिलिटी सुरक्षा पर बनी संसदीय समिति की सभी 28 सिफारिशों को पूरी तरह या सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया गया है। इनमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध भी शामिल है। क्वींसलैंड के परिवहन मंत्री ब्रेट मिकेलबर्न ने कहा कि सरकार जल्द ही इन सिफारिशों को कानून बनाने के लिए संसद में पेश करेगी। नए नियमों के मुताबिक, ई-बाइक और ई-स्कूटर चलाने के लिए कम से कम क्वींसलैंड का लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी होगा। यह लाइसेंस 16 साल की उम्र में मिलता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चलाने वाले को ट्रैफिक नियमों की जानकारी हो। जांच में सामने आया कि साल 2025 में क्वींसलैंड में ई-मोबिलिटी से जुड़े हादसों में 12 लोगों की मौत हुई और 6,300 लोग घायल हुए। मिकेलबर्न ने मंगलवार को कहा कि हम 16 साल से कम उम्र वालों पर इन डिवाइस के इस्तेमाल पर रोक लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। नए कानूनों के तहत फुटपाथों पर ई-मोबिलिटी डिवाइस के लिए 'टेस्ट' (सांस की जांच) भी कर सकेंगे। पिछले साल, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया पर दुनिया का पहला प्रतिबंध लागू हुआ था। इसके तहत फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक और एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को ऐसे बच्चों के अकाउंट बनाने से रोकना होगा।

## अब स्विगी से खाना मंगवाना भी महंगा



नई दिल्ली (एजेंसी)। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने खाना ऑर्डर करने पर लगने वाली प्लेटफॉर्म फीस को बढ़ाकर 17.58 रूपए प्रति ऑर्डर (जीएसटी सहित) कर दिया है, जो पहले 14.99 रूपए थी। स्विगी ऐप की बिलिंग के अनुसार, प्लेटफॉर्म फीस में करीब 17 प्रतिशत या 2 रूपए 59 पैसे का इजाफा हुआ है। इससे पहले स्विगी ने अगस्त 2025 में स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस में करीब 2 रूपए की वृद्धि की थी, जो कि पहले 12 रूपए थी।

## ड्रग्स कंट्रोलर ने जारी की एडवाइजरी



बिना अनुमति बिक्री और प्रचार पर निगरानी होगी तेज नई दिल्ली (एजेंसी)। वजन घटाने वाली दवा (जीएलपी-1) की सप्लाई चेन में नैतिक फार्मास्युटिकल तरीकों को सुनिश्चित करने के लिए भारत के ड्रग्स कंट्रोलर ने दवा की बिना अनुमति बिक्री और प्रचार के खिलाफ अपनी रेगुलेटरी निगरानी तेज कर दी। भारतीय बाजार में जीएलपी-1-आधारित वजन घटाने वाली दवाओं के कई जेनेरिक वेरिएंट के हाल ही में आने के साथ रिटेल फार्मसियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, थोक विक्रेताओं और वेल्नेस क्लीनिकों के माध्यम से उनकी 'मांग' पर उपलब्धता के बारे में चिंताएं सामने आई हैं। जब इन दवाओं का उपयोग उचित चिकित्सकीय देखरेख के बिना किया जाता है, तो इनसे गंभीर दुष्प्रभाव और संबंधित स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। स्थिति का संज्ञान लेते हुए भारत के ड्रग्स कंट्रोलर ने राज्य रेगुलेटरी के सहयोग से फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन में संभावित गलत तरीकों को रोकने और बिना अनुमति बिक्री तथा उपयोग को रोकने के लिए कई लक्षित कार्रवाइयां शुरू की हैं।

## भारत में इस दवा को इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई है कि इसे केवल एंजोक्रिनोलॉजिस्ट (हार्मोन विशेषज्ञ) और इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञों द्वारा ही लिखा जाएगा, और कुछ विशेष स्थितियों में केवल कार्डियोलॉजिस्ट (हृदय रोग विशेषज्ञ) द्वारा ही लिखा जाएगा।

भारत में इस दवा को इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई है कि इसे केवल एंजोक्रिनोलॉजिस्ट (हार्मोन विशेषज्ञ) और इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञों द्वारा ही लिखा जाएगा, और कुछ विशेष स्थितियों में केवल कार्डियोलॉजिस्ट (हृदय रोग विशेषज्ञ) द्वारा ही लिखा जाएगा।

नियमों में इस दवा को इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई है कि इसे केवल एंजोक्रिनोलॉजिस्ट (हार्मोन विशेषज्ञ) और इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञों द्वारा ही लिखा जाएगा, और कुछ विशेष स्थितियों में केवल कार्डियोलॉजिस्ट (हृदय रोग विशेषज्ञ) द्वारा ही लिखा जाएगा।

भारत में इस दवा को इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई है कि इसे केवल एंजोक्रिनोलॉजिस्ट (हार्मोन विशेषज्ञ) और इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञों द्वारा ही लिखा जाएगा, और कुछ विशेष स्थितियों में केवल कार्डियोलॉजिस्ट (हृदय रोग विशेषज्ञ) द्वारा ही लिखा जाएगा।

भारत में इस दवा को इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई है कि इसे केवल एंजोक्रिनोलॉजिस्ट (हार्मोन विशेषज्ञ) और इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञों द्वारा ही लिखा जाएगा, और कुछ विशेष स्थितियों में केवल कार्डियोलॉजिस्ट (हृदय रोग विशेषज्ञ) द्वारा ही लिखा जाएगा।

## एनसीआर में एक बार फिर बदलेगा मौसम, 26 मार्च को गरज के साथ बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)। नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 26 मार्च को तेज हवाओं, तूफान और बारिश की संभावना जताई है। वहीं, 29 मार्च को भी इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इन दिनों तापमान और आर्द्रता में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, वहीं वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में भी आंशिक परिवर्तन दर्ज किया गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 24 मार्च को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दिन आधिक्यता तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 25 मार्च को मौसम लगभग ऐसा ही रहेगा, जिसमें तापमान 32 से 17 डिग्री और आर्द्रता 70 से 30 प्रतिशत रहेगी। हालांकि, 26 मार्च को मौसम करवट बदलेगा। इस दिन आंशिक बादल छाए रहने के साथ गरज के साथ बारिश ( थंडरस्टॉर्म विद रेन) होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग ने इन तीनों दिनों के लिए किसी प्रकार की कोई चेतावनी जारी नहीं की है। दूसरी ओर, वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में हवा की स्थिति 'खराब' से 'बहुत खराब' की श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार, आनंद विहार में एक्यूआई 247 दर्ज किया गया, जो सबसे अधिक रहा। चांदनी चौक में 226, बवाना में 200, आलीपुर में 180, कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 171, अशोक विहार में 163, बुराड़ी कॉम्प्लेक्स में 162, कैंटोनेमेंट परिया में 151, सीआरआरआई मयपुर रोड पर 137 और डॉ. कर्णो सिंह शूटिंग रेंज में 128 एक्यूआई दर्ज किया गया। नोएडा की बात करें तो यहां सभी चार स्टेशन सक्रिय हैं। सेक्टर-125 में एक्यूआई 240, सेक्टर-116 में 207, सेक्टर-1 में 200 और सेक्टर-62 में 139 दर्ज किया गया। वहीं गाजियाबाद में लोनी सबसे प्रदूषित रहा, जहां एक्यूआई 246 दर्ज किया गया। वसुंधरा में 235, इंदिरापुरम में 198 और संजय नगर में 161 एक्यूआई रहा। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, 26 मार्च को होने वाली बारिश और तेज हवाओं से प्रदूषण के कणों में कमी आ सकती है, जिससे एक्यूआई में सुधार होने की संभावना है।

## बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के प्लाईवुड गोदाम में लगी आग, 17 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशकत के बाद पाया काबू

नई दिल्ली (एजेंसी)। बवाना सेक्टर-2 औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक प्लाईवुड गोदाम में मंगलवार तड़के भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। किसी के हाताहत की कोई सूचना नहीं है। दमकल विभाग के अनुसार, आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे क्षेत्र में धुंध का गुबार छा गया और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) को सुबह करीब 3:55 बजे मिली, जिसके बाद तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। शुरुआती तौर पर तीन पानी की गाड़ियां, दो पानी के टैंकर और एक त्वरित प्रतिक्रिया वाहन मौके पर भेजे गए। हालांकि, गोदाम के अंदर भारी मात्रा में ज्वलनशील प्लाईवुड और अन्य सामग्री रखी होने के कारण आग तेजी से फैलने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग ने चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त फायर टैंकर को मौके पर भेजा। कुल 17 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाला है। घटनास्थल पर पहुंची दमकल टीमों ने तुरंत आग बुझाने का अभियान शुरू किया और कई घंटों तक की मशकत के बाद आग पर आंशिक नियंत्रण पाया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास की फैक्ट्रियों को भी खतरा उत्पन्न हो गया था, लेकिन समय रहते दमकलकर्मियों ने स्थिति को विंगडन से रोक लिया। इस दौरान राहत कार्य में जुटे एक दमकलकर्मियों, अधिकारी प्रशांत, के हाथ में मामूली घात लगा गई। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुड़ी दे दी गई। अधिकारियों ने बताया कि उनकी हालत अब पूरी तरह से ठीक है। दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट या अन्य तकनीकी कारणों की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल, आग पर पूरी तरह काबू पाने और क्विंटग ऑपरेशन का काम जारी है। घटना के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है और आसपास के औद्योगिक इकाइयों को भी सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस हादसे में किसी के हाताहत होने की खबर नहीं है, जो राहत की बात है। हालांकि, गोदाम में रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचा है।

## पालम अग्निकांड का मुद्दा उठा रास में : आप सांसद संजय सिंह ने जवाबदेही तय करने की मांग की

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजधानी दिल्ली के पालम इलाके में बीते सप्ताह हुए अग्निकांड का मुद्दा उठाते हुए राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मंगलवार को कहा कि प्रशासनिक लापरवाही के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। शुरुआत में यह मुद्दा उठाते हुए सिंह ने कहा कि इस अग्निकांड में एक ही परिवार के नौ सदस्य मारे गए। इससे पता चलता है कि आम कितनी भयावह रही होगी। उन्होंने कहा कि लेकिन डिब्बाना यह है कि वहां जब दमकल पाए पहुंचा तो उसकी हाइड्रोलिक सीढ़ी खुल नहीं रही थी तथा अग्निशमन कर्मियों के पास सफाई की जल भी नहीं था। उन्होंने कहा " बवाल में ही गंदे की दुकान थी। गंदे की दुकान वाला बार बार करता रहा कि हम यहां गद्दा लगा देते हैं, बच्चे ऊपर से उतर पर कूद कर बच जायेंगे। लेकिन वहां पर यह नहीं लगाने दिये गये। और एक ही परिवार के नौ लोग असमय काल के माल में समा गये। इस प्रशासनिक लापरवाही के लिए अग्निशमन कर्मियों को जिम्मेदार है?" उन्होंने कहा " बाबू इतनी ही नहीं है। कल दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने कहा कि गलती तो उसी परिवार की थी जिसने अपनी दुकान में कॉम्पैक्टिक्स आदि रखा था जिसमें आग लगने से यह हादसा हुआ।" आप सदस्य ने कहा " यह तो हद हो गई। इतनी क्रूरता आप लाते कहा से है?" सिंह ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल वहां शोक व्यक्त करने गए तो वहां व्यवधान डाला गया, हंगामा किया गया। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की गहन जांच की जानी चाहिए, प्रशासनिक लापरवाही को लेकर जवाबदेही तय की जानी चाहिए तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

## यमुना एक्सप्रेसवे हादसा मामले में महिला की मौत पर बेंटी को मिलेगा 29.27 लाख मुआवजा

नई दिल्ली (एजेंसी)। द्वारका कोर्ट के मोटर एक्सीडेंट वलेम टिब्यूनल ने यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाली एक महिला की बेंटी को 29 लाख 27 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने महिला की आग का अनुमान न्यूनतम मकदूरी के आगे पर लाया और उनकी बेंटी को आंशिक माने हुए मुआवजे की राशि तय की। अदालत ने कुल 29.27 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिस पर 7 सितंबर 2021 से 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज भी मिलेगा। साथ ही, अदालत ने निर्देश दिया कि यह पूरी राशि बेंटी के नाम सुरक्षित खाते एफडीआर/एन्यूटी में जमा की जाएगी, जो 20, 18 साल की उम्र पूरी होने पर मिलेगी। अदालत ने परिवहन निगम को 30 दिनों के भीतर यह राशि जमा करने का आदेश दिया है। यह हादसा 28 मार्च 2021 को हुआ था। पिराका निवासी वंदाना से दिल्ली लौट रही थी, तभी एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 99 के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने उसकी कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि दुर्घटना बस चालक की लापरवाही से हुई और बस मालिक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम भी इसके लिए जिम्मेदार है।

## निवेश के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 11 साइबर टग दिल्ली और मुंबई से गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस की साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफास किया है, जो वरिष्ठ नागरिकों को निवेश पर भारी रिटर्न का लालच देकर चत चलाते थे। पुलिस ने दिल्ली और मुंबई में छापेमारी कर गिरोह के 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में कनिंद्र, आशीष, शिव दयाल, शिवा, गिरिराज, प्रतिभा, सतीश, रामदेव, प्रवीण, दीपक और त्रिलोक चंद शामिल हैं। पुलिस अब इस गिरोह के अंतरराष्ट्रीय संपर्कों और कंबोडिया में बैठे इनके आकाओं की तलाश कर रही है। इनके पास से 40 मोबाइल फोन, 92 फर्जी सिम कार्ड, 39 चेकबुक और भारी मात्रा में एटीएम कार्ड व डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं। साथ ही दो पीओएस मशीनें, छह यूपीआई स्कैनर और कंपनियों के रजिस्टर्ड नंबर बदलने के फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार इस गिरोह की कार्यणाली बेहद शांति थी। इन्होंने एक फेसबुक विज्ञापन के जरिए ए. श्रीनिवासन नामक बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया। विज्ञापन में वित्त मंत्री के भाषण का दुरुपयोग कर एआइ आधारित टोंडिंग का प्रचार किया गया था। शिकायतकर्ता को मुद्रान वन 9पीआरओ जैसे फर्जी एप्स पर रजिस्टर्ड कराकर निवेश के लिए उतसाहता गया। आरोपितों ने खुद को निवेश सलाहकार बताकर श्रीनिवासन से कुल 22.67 लाख रुपये टग लिए और उसके बाद सभी संवार माध्यम बंद कर दिए।

# दिल्ली बजट 2026: 1.03 लाख करोड़ का 'ग्रीन बजट' पेश, पर्यावरण पर खास फोकस



नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए राजधानी के विकास के लिए कई बड़े एलान किए। इस बार सरकार ने 1 लाख 3 हजार 700 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जिसे पिछले साल के मुकाबले काफी बड़ा बताया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि इस बजट को लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 'ग्रीन बजट' के रूप में तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट की हर योजना और नीति में पर्यावरण संरक्षण

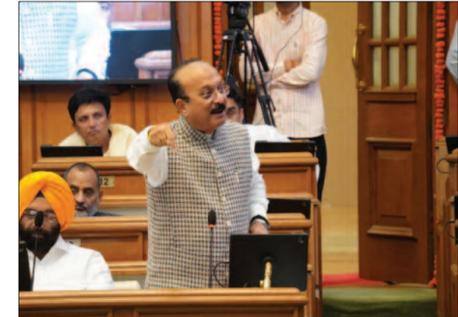
के लिए रखा गया है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के लिए इस बार बड़ा प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार 11,666 करोड़ रुपये की राशि एमसीडी को दी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास को भी बजट में प्राथमिकता दी गई है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के लिए 5,921 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा, शहरी विकास के लिए 7,887 करोड़, यमुनानगर के लिए 300 करोड़, झुग्गी विकास के लिए 800 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 787 करोड़ और विकास विभाग

# राष्ट्रीय संकट में एकजुटता जरूरी, सरकार का सहयोग करें : अभिमन्यु गुलाटी

नई दिल्ली (एजेंसी)। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर उभरती चुनौतियों के बीच देश में एकजुटता और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में यूएफएस राइट फंड के अध्यक्ष एवं समाजसेवी अभिमन्यु गुलाटी ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में सभी नागरिकों को अपने वैचारिक मतभेद भुलाकर सरकार का साथ देना चाहिए, ताकि संभावित संकटों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। अभिमन्यु गुलाटी का यह बयान उस समय आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मध्य पूर्व की स्थिति को भारत के लिए 'अप्रत्याशित चुनौतियों'

जैसे पारंपरिक ईंधनों के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों और विद्युत आधारित खाना पकाने के साधनों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने निजी चाहनों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण लगाने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की आवश्यकता बताई। उनके अनुसार, बसों, रेलगाड़ियों और मेट्रो सेवाओं के अधिक उपयोग से न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता भी कम होगी। गुलाटी ने कार्य संस्कृति में

## दिल्ली वालों के सपनों को साकार करने वाला बजट : सूद



नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली, 24 मार्च (वेब वार्ता)। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूदन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आज 2026-27 का हरित बजट पेश किया है। यह जनहितकारी बजट दिल्ली के लोगों के कल्याण के साथ-साथ उनके सपनों को साकार करने वाला बजट भी है। सूदन ने कहा कि दिल्ली का बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि यह बिजली, सड़क, परिवहन जैसे आर्थिक क्षेत्रों और शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण जैसे सामाजिक क्षेत्रों की दिशा और दशा तय करता है। वर्ष 2024-25 में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान जहां बजट मात्र 76,000 करोड़ रुपये था, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर 1,00,000 करोड़ रुपये हुआ और अब 2026-27 में 1,03,700 करोड़ रुपये का है। जो यह दर्शाता है की दिल्ली सरकार विकास के कार्य निरंतर कर रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास में कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंस (पूँजीगत व्यय) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 2024-25 में जहां यह 15,089 करोड़ रुपये था, वहीं 2025-26 में बढ़कर 28,115 करोड़ हुआ और 2026-27 में 30,800 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है—जो मजबूत बुनियादी ढांचे और दीर्घकालिक विकास का संकेत है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि दिल्ली की आर्थिक विकास दर 2025-26 में 8.53 फीसद तक पहुंच गई, जो 7.4 फीसद के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसके विपरीत, 2024-25 में यह 6.21 फीसद थी, जो राष्ट्रीय औसत 6.5 फीसद से कम थी। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। 2024-25 में जहां औसत मासिक आय 23,676 रुपये थी, वह 7,098 प्रति व्यक्ति के साथ 2025-26 में 25,453 हो गई—जो नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार का स्पष्ट प्रमाण है। सूदन ने कहा कि यह जनभावनाओं और जनआपेक्षाओं से जुड़ा हुआ बजट है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में ऐतिहासिक प्रगतिजनक करने पर कहा कि इस वर्ष के बजट में शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र के लिए 19,148 करोड़ का सर्वाधिक प्रावधान (जो कुल बजट का 18.64 फीसद है) सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। कक्षा 9 की बालिकाओं के लिए मुफ्त सांस्कृतिक योजना सरकार का एक सराहनीय पहल है, जो बालिका शिक्षा को नई दिशा देगी। इस मद पर 90 करोड़ रुपये का व्यय होगा। प्रत्येक सरकारी स्कूल में मेडिकल रूम की स्थापना, छात्रों के लिए फ्रैक्चरब्रेजिंग रिजिटिफिकेशन और शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हेतु 10 करोड़ का प्रावधान—ये सभी कदम भविष्य उन्मुख हैं। इस बजट में नए बनें के निर्माण के लिए 200 करोड़ तथा स्कूलों के विस्तार के लिए 275 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स हॉस्टल, खेल मैदान और स्विमिंग पूल के निर्माण के लिए 50 करोड़ आवंटित किए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि तकनीकी शिक्षा के लिए इस बजट में 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजट के माध्यम से सरकार शिक्षा के युवाओं को जीब सिकर नहीं बल्कि बूट क्रेपर बनाना चाहती है। सरकार स्टार्टअप और इन्क्यूबेशन पॉलिसी के माध्यम से इनोवेशन को प्रोत्साहित भी तैयार करने जा रही है। सरकार ने पहली बार बजट में प्रॉब्लेम टूल्स स्कूल पॉलिसी और प्रॉब्लेम टूल्स अकेडमी पॉलिसी बनाने का भी प्रावधान किया है। बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 150 करोड़ रुपये के आवंटन से 8,777 स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जाएंगे। आने वाले समय में 21000 स्मार्ट कक्षाओं तक इसका विस्तार किया जाएगा। नरेला में जुड़ोकेस हब के विकास को गति दी जाएगी और मुद्राका में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना से दिल्ली को एक उभरते हुए स्पोर्ट्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

# दिल्ली में बंद घरों में चोरी करने वाले एक फैमिली गैंग का भंडाफोड़, भाई-भाभी और बहन गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। दक्षिणी दिल्ली के महरोली थाना क्षेत्र में घरों में चोरी की कई वारदातों के अंजाम देने वाले एक परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान कर्मवीर, उसकी भाभी पलक और बहन राधिका उर्फ राधा के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला कि आरोपित अब तक चोरी के पांच लाख रुपये के आभूषण बेच चुके हैं, जिनकी उनके पास से रसीदें बरामद हुई हैं। इसके अलावा लैपटॉप और दो मोबाइल समेत जूलीर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़े भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने उनके अकाउंट में जमा एक लाख रुपये फ्रीज कर दिए हैं। जांच में यह भी पता चला है कि आरोपित के कर्मवीर के ऊपर पहले से 31 से अधिक मामले दर्ज हैं और वह तिगड़ी का घोषित बदमाश (बीसी) भी है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से चोरी के सात मामलों को सुलझाने का दावा किया है। दक्षिणी जिले के उपायुक्त अनंत मित्तल के मुताबिक, 16 मार्च को महरोली स्थित एक बंद घर में चोरी की सूचना मिली थी। एस्प्रेसओ महरोली रिपेश शर्मा की देखरेख में गाँवट टीम ने मामले की जांच की तो पता चला कि पिछले कुछ समय में इसी पैटर्न पर इलाके में चोरी की वारदात हो रही है। पुलिस



टीम ने चोरी के सभी घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने शुरू किए। जांच में पता चला कि सभी वारदात में एक आदमन अपराधी शामिल है। आरोपित की पहचान कर्मवीर के रूप में हुई। पुलिस टीम ने उसके संबंध में जानकारी जुटानी शुरू की। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपित कर्मवीर को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ के बाद वारदात में उसका साथ देने के आरोप में भाभी और

## आप के चार विधायकों का निलंबन उनके असंसदीय आचरण का परिणाम : विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी (आप) के चार सदस्यों के निलंबन को लेकर इस बात पर जोर दिया कि सदन और असन की गरिमा को राजनीतिक हितों से ऊपर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विगत जनवरी में शीतकालीन सत्र के दौरान सदस्यों को निलंबित करने का निर्णय मनमाना नहीं था, बल्कि उनके निरंतर अदोलेन, दुर्व्यवहार और उपराज्यपाल के अभिभाषण जैसे गरिमापूर्ण अवसर पर उनके द्वारा डाले गए व्यवधान का एक आवश्यक परिणाम था। विजेंद्र गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष आतिशो को एक औपचारिक पत्र जारी कर 'उदंड सदस्यों' के बनाव और विपक्ष द्वारा प्रदर्शित 'असंसदीय आचरण' पर अपनी गहरी निराशा व्यक्त की। विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को याद दिलाया कि चार सदस्यों का निलंबन पूरी तरह से दिल्ली विधानसभा की प्रक्रिया के नियमों के अनुरूप था। उन्होंने उल्लेख किया कि इन सदस्यों को शुरू में उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा को संबोधित करने के संवैधानिक कर्तव्य में बाधा डालने के लिए निलंबित किया गया था। अध्यक्ष ने रेखांकित किया कि ऐसे व्यवहार की निंदा करने के बजाय विपक्ष ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए निलंबन के कारणों के बारे में 'भ्रामक जानकारी' फैलाने का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि 21 मार्च को इंडियन टैक के दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को विशेष रूप से सलाह दी थी कि वे सदन की बैठक में उपस्थित रहें और निलंबन वापसी के मामले पर सदन को निर्णय लेने दें। इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष ने कार्यवाही से दूर रहने का फैसला किया। पत्र के अनुसार नेता प्रतिपक्ष को अपनी पार्टी के सदस्यों की विफलताओं और आपत्तिजनक व्यवहार को छिपाने के लिए अध्यक्ष और सदन को चरसीना शोभा नहीं देता। उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा के जनवरी में हुए शीतकालीन सत्र के दौरान उपराज्यपाल के अभिभाषण में बाधा डालने और सदन में असंसदीय आचरण के आरोप में आप के चार विधायकों— संजीव झा, कुलदेव कुमार, सोमदत्त और जयनल सिंह को निलंबित किया गया था। यह निलंबन अब भी जारी है, जिसके विरोध में आप ने मौजूदा बजट सत्र के बहिष्कार की चेतावनी दी थी। मौजूदा बजट सत्र में आप के कोई सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। विजेंद्र गुप्ता ने अपने ऊपर लगे सलाहवादी या पक्षपाती होने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनकी अध्यक्षता में वर्तमान सदन पिछले वर्षों की तुलना में विपक्षी सदस्यों के प्रति अधिक सहनशील और उदार रहा है।

# दिल्ली बजट 2026 पर कांग्रेस का हमला: 'ट्रिपल इंजन सरकार का ट्रिपल धोखा': देवेंद्र यादव

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने वर्ष 2026-27 के दिल्ली बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे 'ट्रिपल इंजन सरकार के दो बजट में ट्रिपल धोखा' कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट भ्रष्ट, वर्तमान और भविष्य-तीनों के साथ विश्वासघात करता है तथा आम जनता को केवल आश्वासनों तक सीमित रखता है। देवेंद्र यादव ने कहा कि राजधानी का बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह शहर के विकास की दिशा तय करता है। हालांकि, उनके अनुसार प्रस्तुत बजट में ठोस नीतियों और स्पष्ट कार्ययोजना का अभाव दिखाई देता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सदन में प्रभावी विपक्ष के अभाव के कारण सरकार जवाबदेही से

बच रही है। उन्होंने वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपये के बजट में बड़े पैमाने पर कर्ज लेने का प्रावधान किया गया है, जबकि पिछले वर्ष आवंटित बजट का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं किया गया। संशोधित अनुमान के अनुसार सरकार राजस्व लक्ष्य हासिल करने में भी विफल रही, जिससे कई योजनाएं केवल घोषणा तक सीमित रह गईं। पर्यावरण और 'ग्रीन बजट' को लेकर भी उन्होंने सरकार की आलोचना की। यादव ने आरोप लगाया कि ग्रीन बजट के नाम पर वास्तविक आवंटन में कटौती की गई है और पिछले वर्ष भी पर्यावरण से जुड़ी योजनाओं पर बहुत कम खर्च हुआ। उन्होंने इसे 'पर्यावरण

## दिल्ली बजट पेश करने से पहले विधानसभा को मिली बम से उड़ाने की धमकी, चप्पे-चप्पे की जांच



मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के नाम थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हस्तगत में आ गईं। विधानसभा परिसर और आसपास के इलाके की गहनता से जांच शुरू की गई। डॉ. स्कॉट और बम निरोधक टीम ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में विस्तार से जांच की। पुलिस ने आसपास के मेट्रो स्टेशन की भी जांच तेज कर दी, ताकि अगर किसी तरह की कोई संदिग्ध चीज हो तो पकड़ी जा सके। सुरक्षा कार्यों से विधानसभा की कार्यवाही को 11:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल किसी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। हालांकि सुरक्षा में कोई कमी न रहे, इसके लिए पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी है। विधानसभा में बजट 2026 पेश करने वाली है। इसी बीच विधानसभा को बम उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने लगभग जांच पूरी कर ली है। अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। ऐसे में सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा में पहुंच कर अलर्ट पेश कर रही हैं।

# संभव के तहत नगर निगम मुख्यालय पर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई जनसुनवाई

**गाजियाबाद (शिखर समाचार)।** नगर निगम मुख्यालय पर नगर आयुक्त विक्रमसिंह सिंह मलिक की अध्यक्षता में संभव के तहत जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान निगम अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे। विशेष रूप से अपर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव, प्रभारी उद्यान डॉक्टर अनुज, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एसके राय, प्रभारी प्रकाश आश कुमार, निर्माण विभाग से एसपी मिश्रा व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। संभव के

दौरान 9 शिकायत प्राप्त हुए, जिसमें निर्माण विभाग से दो, उद्यान विभाग का एक, संपत्ति विभाग से एक, टैक्स विभाग से दो, अतिक्रमण संबंधित दो व अन्य विभाग से एक शिकायत प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायत पर नगर आयुक्त ने अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर टीम भी भेजी गई। हाउस टैक्स के प्राप्त दो शिकायत पर जांच करते हुए कार्यवाही प्रारंभ की गई। संभव में



प्राप्त शिकायत के गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण के लिए नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त जंग बहादुर यादव को निर्देशित किया गया। साथ ही मॉनिटरिंग को प्रबल करने के लिए कहा गया। वसुंधरा, सेक्टर 23 संजय नगर, न्यू आर्य नगर शिवनपुरा, साहिबाबाद, गोविंदपुरम, विजयनगर से आगंतुकों ने अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याओं को रखा तथा समाधान के लिए कार्यवाही प्रारंभ की गई।

## जीडीए का महा अभियान : डासना और मसूरी में अवैध कॉलोनीयों पर गरजा बाबा का बुलडोजर

**आरव शर्मा**  
**गाजियाबाद (शिखर समाचार)** गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने भूमाफियाओं और अवैध कॉलोनीजनों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। मंगलवार को उपाध्यक्ष के कड़े निर्देशों के अनुपालन में प्रवर्तन जोन 03 की टीम ने डासना और मसूरी क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ धावा बोला। इस दौरान करीब 23000 वर्ग मीटर वेशकीमती जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनीयों को मलबे में तब्दील कर दिया गया।

**विरोध के बावजूद जारी रहा ध्वस्तीकरण**  
प्रवर्तन जोन 03 के प्रभारी के नेतृत्व में चली इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय निर्माणकर्ताओं और कॉलोनीजनों ने सरकारी काम में बाधा डालने और विरोध करने का प्रयास किया। माहौल को गरमाता देख प्राधिकरण पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शककारियों को खदेड़कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी रखी। इन क्षेत्रों में हुई बड़ी कार्रवाई प्राधिकरण की टीम ने अलग अलग



**खसरा नंबरों पर बने अवैध ढांचों को निशाना बनाया:**  
ग्राम मसूरी (खसरा संख्या-582): सुभान द्वारा लगभग 3,000 वर्ग मीटर में किए गए अवैध विकास कार्य को ध्वस्त किया गया।  
कुशालिया, डासना (खसरा संख्या-1635): पवन चौधरी और इस्लाम द्वारा करीब 5,000 वर्ग मीटर में काटी जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चला।  
डासना मुख्य हापुड़ रोड: फोरस्ट पार्क टाउनशिप और कल्लू गढ़ी रोड के मध्य करीब 3,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाया गया।  
रेलवे फाटक रोड (डासना स्टेशन के पीछे): ललित चौधरी और रविन्द्र

चौधरी द्वारा संकेतिक विशेष माध्यमिक विद्यालय के सामने करीब 8,000 वर्ग मीटर में किए गए निर्माण को जमींदोज किया गया।  
मसूरी झील रोड: जेल इंडिया के सामने शुभान, फजरुद्दीन, रहमान और फरमान द्वारा करीब 4,000 वर्ग मीटर में किए जा रहे अवैध विकास कार्य पर पीला पंजा चला।  
**सड़कें और ऑफिस किए ध्वस्त**  
जीडीए की टीम ने इन अवैध कॉलोनीयों में बनाई गई सड़कों, बाउंड्रीवॉल, साइट ऑफिस और अन्य अवैध ढांचों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस अभियान के दौरान स्थल पर सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर, मेट और स्थानीय पुलिस बल के साथ भारी संख्या में प्राधिकरण का पुलिस बल तैनात रहा।  
**जीडीए की चेतावनी:** प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए या अवैध रूप से किए जा रहे किसी भी निर्माण को चख्खा नहीं जाएगा। जनता से भी अपील की गई है कि वे ऐसी अवैध कॉलोनीयों में निवेश न करें।

## गैस सिलेंडर न मिलने पर भड़के उपभोक्ता, दिल्ली मेरठ मार्ग पर लगाया जाम, लंबी कतारों से थमा यातायात

**मोदीनगर (शिखर समाचार)।** रसोई गैस की बुकिंग कराने के बावजूद समय पर सिलेंडर न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं का गुस्सा मंगलवार को सड़कों पर उतर आया। आक्रोशित लोगों ने गैस एजेंसी के बाहर दिल्ली मेरठ मार्ग पर जाम लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली मेरठ मार्ग पर मोदी मंदिर के सामने स्थित धीरेद गैस एजेंसी पर मंगलवार दोपहर बड़ी संख्या में उपभोक्ता गैस सिलेंडर लेने पहुंचे थे। इन सभी ने पहले से ही गैस की बुकिंग करा रखी थी, लेकिन एजेंसी पर पहुंचने के बाद उन्हें सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे यहां मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि एजेंसी संचालक द्वारा जानबूझकर बुकिंग के बावजूद सिलेंडर वितरण नहीं किया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर सिलेंडरों की कालाबाजारी की जा रही है। लोगों का कहना था कि उन्हें कई दिनों से गैस नहीं मिल रही है, जिससे उनके घरों में खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष रूप से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति बिगड़ती देख लोगों ने मौके पर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने की मांग की, लेकिन काफी देर तक कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचा। इससे नाराज होकर उपभोक्ता और अधिक उग्र हो गए और एजेंसी के सामने से गुजर रहे दिल्ली मेरठ मार्ग पर पहुंचकर जाम लगा दिया। जाम लगते ही मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करने का प्रयास



किया। प्रारंभ में लोग मानने को तैयार नहीं हुए और कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे, लेकिन काफी देर तक चली समझाइश और उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम खोल दिया, जिसके बाद यातायात धीरे धीरे सामान्य हो सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि उक्त गैस एजेंसी पर इस तरह की शिकायतें कोई नई बात नहीं हैं। पहले भी कई बार सिलेंडर वितरण को लेकर हंगामा हो चुका है। शिकायतों के आधार पर संबंधित अधिकारियों द्वारा गैस गोदाम पर छापेमारी भी की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि तीन दिन पूर्व भी एजेंसी संचालक के विरुद्ध इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज की गई थी, इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उपभोक्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि गैस वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए और दोषी एजेंसी संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

## जनरेटर से फैल रहे प्रदूषण की मुख्यमंत्री से शिकायत, कार्रवाई की मांग

**मोदीनगर (शिखर समाचार)।** दिल्ली मेरठ मार्ग स्थित डॉ. केएन मोदी कॉम्प्लेक्स में एक जनरेटर से फैल रहे प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री से शिकायत की गई है। मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में दुकान संख्या 27ए, आकांक्षा इलेक्ट्रिक के संचालक रामपाल सिंह ने बताया कि उनकी दुकान से सटी एक अन्य दुकान में संचालित रेस्टोरेंट के बाहर, कवर्ड नाले के ऊपर भारी भरकम जनरेटर रखा गया है। आरोप है कि इस जनरेटर से निकलने वाला धुआं और शोर आसपास के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, जिससे उनकी दुकान पर ग्राहकों का आना लगभग बंद हो गया है। इसी कारण उन्हें लंबे समय से अपनी दुकान बंद रखनी पड़ रही है, जिससे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। रामपाल सिंह ने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि जनरेटर को हटवाने के लिए उन्होंने जिलाधिकारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप कर इस समस्या का समाधान कराने और जनरेटर को वहां से हटवाने की मांग की है, ताकि क्षेत्र में प्रदूषण से राहत मिल सके और उनका व्यापार पुनः शुरू हो सके।

## नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस का अभियान, 2 किलो गांजे के साथ महिला गिरफ्तार

**बिजनौर (शिखर समाचार)।** जनपद में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक अहम सफलता हाथ लगी है। स्योहरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को लगभग 2 किलोग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर के माध्यम से क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बिक्री की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के गांव सदाफल में दबिश दी। दबिश के दौरान हुसन जहां नामक महिला को हिरासत में लिया गया। तलाशी लेने पर महिला के कब्जे से करीब 2 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर आरोपी महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार मामले की गहनता से जांच की जा रही है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बरामद नशीला पदार्थ कहाँ से लाया गया था और इस अवैध कारोबार में महिला के साथ अन्य कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

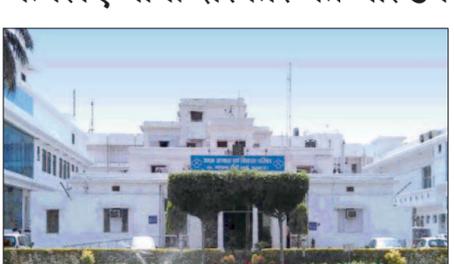


## मंडलायुक्त का प्रस्तावित दौरा अचानक स्थगित, तैयारियां धरी रह गईं

**नगीना/बिजनौर (शिखर समाचार)।** मुरादाबाद मंडल के आयुक्त का प्रस्तावित नगीना दौरा मंगलवार को अचानक स्थगित हो जाने से प्रशासनिक अमले की एक सप्ताह से चल रही तैयारियां बेकार साबित हो गईं। दौरा निरस्त होने की सूचना मिलते ही अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली, वहीं दूसरी ओर की गई व्यापक तैयारियां धरी की धरी रह गईं। मंडलायुक्त द्वारा नगर पालिका परिषद, एसडीएम न्यायालय और तहसील नगीना का निरीक्षण किया जाना था था। दौरे की सूचना मिलते ही पिछले एक सप्ताह से संबंधित विभागों में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही थीं। एसडीएम न्यायालय, तहसील परिषद और नगर पालिका परिषद के दफतरो में रंगाई-पुताई कराई गई, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया और लंबित फाइलों को दुरुस्त करने का कार्य तेज कर दिया गया था। अधिकारी और कर्मचारी लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जुटे हुए थे। मंगलवार को जैसे ही मंडलायुक्त का दौरा स्थगित होने की सूचना मिली, प्रशासनिक हलकों में हलचल थम गई। दिनभर अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में मौजूद रहे, लेकिन निरीक्षण न होने से सभी तैयारियां व्यर्थ चली गईं। दूसरी ओर, मंडलायुक्त के दौरे को लेकर समाजसेवी, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, नगर पालिका के निर्वाचित व नामित सभासद भी बेसहरी से इंतजार कर रहे थे। सभी ने अपनी-अपनी समस्याओं और नगर विकास से जुड़े मुद्दों के ज्ञान पहले से तैयार कर रखे थे, लेकिन दौरा स्थगित होने से उन्हें भी निराशा हाथ लगी।



## यूपी के संपत्ति स्वामियों की हुई चांदी : ब्याज और जुमाने से मुक्ति के लिए योगी सरकार की गोल्डन स्क्रीम (OTS-2026) का ऐलान



**आरव शर्मा**  
**लखनऊ/गाजियाबाद (शिखर समाचार)।** उत्तर प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने प्रदेश भर के लाखों संपत्ति आवंटियों को एक बड़ी राहत देते हुए 'एकमुद्रत समाधान योजना (ओटीएस) 2026' को मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब आवास एवं विकास परिषद और सभी विकास प्राधिकरणों के आवंटित अपने पुराने बकाये को बिना किसी भारी जुमाने के चुका सकेंगे।  
**इन संपत्तियों पर मिलेगी बड़ी छूट**  
यह राहत योजना केवल घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा बेहद व्यापक रखा गया है।  
**आवासीय संपत्तियां:** आवंटन या नीलामी पद्धति से लिए गए सभी

भवन और भूखंड  
व्यावसायिक संपत्तियां: दुकानें, शोरूम और अन्य व्यावसायिक निर्माण  
संस्थागत संपत्तियां: स्कूल चैरिटेबल संस्थाएं और सरकारी संगठनों को आवंटित जमीनें  
ग्रुप हाउसिंग और समितियों: सहकारी आवास समितियों और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर भी यह योजना लागू होगी  
मानचित्र प्रकरण: नक्शा पास कराने के सापेक्ष रुके हुए बकाये पर भी लाभ मिलेगा  
**ब्याज का बोझ खत्म, मिलेगा एक्स्ट्रा बोनस**  
**जुमाना माफ:** आवंटियों से किसी भी प्रकार का दंड ब्याज नहीं लिया जाएगा। केवल साधारण ब्याज देव

## संपत्ति प्रबंधक का पक्ष : यह बकायेदारों के लिए अंतिम और सुनहटा अवसर

योजना के क्रियान्वयन और आवंटियों की सुविधा पर प्रकाश डालते हुए संपत्ति प्रबंधक पी. एस. रावत ने कहा कि शासन की मंशा जनता को राहत देने और विवादों को खत्म करने की है। उन्होंने विस्तार से बताया कि इस योजना के माध्यम से हम उन सभी आवंटियों को एक मंच पर ला रहे हैं, जो भारी ब्याज के कारण अपना बकाया नहीं भर पा रहे थे। अब उन्हें किसी भी प्रकार का दंडात्मक ब्याज (दंड ब्याज) नहीं देना होगा, हमारी टीम हेलप डेस्क के माध्यम से हर आवेदक की सहायता करेगी ताकि ऑनलाइन आवेदन में कोई बाधा न आए। यह एक सीमित समय की योजना है, इसलिए भेरी सलाह है कि सभी पात्र आवंटित समय रहते इसका लाभ उठाएं और बांधियों को कानूनी पेचिदगियों से बचें। संपत्ति प्रबंधक पी. एस. रावत ने सभी बकायेदारों से अपील करते हुए कहा कि वे शासन/परिषद की इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय रहते अपने बकाये का निस्तारण कराएं।



समय मिलेगा।  
किस्त सुविधा: 50 लाख तक के बकाये को 4 महीने में और 50 लाख से ऊपर के बकाये को 7 महीने में चुकाने की सुविधा दी गई है।  
सावधान: शासन ने स्पष्ट किया है कि योजना की समय-सीमा समाप्त होने के बाद बकाया राशि की वसूली भू राजस्व की भांति सख्ती से की जाएगी और बकायेदारों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

## जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित, आयुष्मान कार्ड व टीकाकरण पर जोर



**बिजनौर (शिखर समाचार)।** मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति (शासी निकाय) की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति और विभिन्न योजनाओं की स्थिति का विस्तृत आकलन किया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिए कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत छूटे हुए सभी पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनाए जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल पात्र व्यक्तियों के ही कार्ड बनें, अपात्र व्यक्तियों का किसी भी स्थिति में पंजीकरण न हो। उन्होंने शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों का शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। साथ ही बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के नियमित टीकाकरण और बच्चों में कुपोषण की स्थिति की समय समय पर जांच कर उसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान चिकित्सालयों में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता, एंटी स्नेक इंजेक्शन की उपलब्धता, आस्था कार्यकर्ताओं के भुगतान, आयुष्मान कार्ड निर्माण तथा प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को समय पर भुगतान की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया कि जर्नाल से जुड़ी सभी स्वास्थ्य सेवाएं निर्धारित मानकों के अनुसार प्रभावी ढंग से संचालित की जाएं। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी तथा सभी चिकित्सा प्रभारी उपस्थित रहे।

## भाजपा जिलाध्यक्ष व कार्यकारिणी का विधायक कैंप कार्यालय पर हुआ स्वागत, शॉल ओढ़ाकर किया सम्मान

**शामली (शिखर समाचार)।** सदर विधायक प्रसन चौधरी द्वारा अपने कैंप कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष रामजीलाल कश्यप एवं उनकी जिला कार्यकारिणी के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर विधायक एवं उनके समर्थकों ने जिलाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मंगलवार को आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लिसाडू खाप के विधायक प्रसन चौधरी ने की, जबकि संचालन मास्टर नीटू कश्यप ने किया। कार्यक्रम में जिला कार्यकारिणी के सदस्यों सहित विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान किया। इस दौरान विधायक प्रसन चौधरी



और जिलाध्यक्ष रामजीलाल कश्यप ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंच रहा है। कार्यक्रम के अंत में विधायक ने जिलाध्यक्ष, खाप चौधरियों एवं बाबा थावेदारों को शॉल ओढ़ाकर

सम्मानित किया। इस अवसर पर बाबा राजकुमार कश्यप, बाबा श्यामू कश्यप, बाबा वीरा कश्यप, बाबा वेदू कश्यप, ऋषिपाल सिंह, छोटन कश्यप, संजीव कश्यप, अरविंद झाल, वीर सिंह मलिक, पवन कश्यप सहेटा, डॉ. कंवरपाल कश्यप टिटौली, महेंद्र सिंह कश्यप झाल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

## पेपर मिल में स्कूली बच्चों ने किया शैक्षणिक अवलोकन, रीसाइक्लिंग प्रक्रिया को समझा



**खतौली/मुजफ्फरनगर (शिखर समाचार)।** राष्ट्रीय अविष्कार योजना के अंतर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी खतौली पंकज अग्रवाल के नेतृत्व में विकास क्षेत्र खतौली के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों का एक शैक्षणिक दल जिनस पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड, मुजफ्फरनगर में एक्सपोजर विजिट पर पहुंचा। इस दौरान बच्चों ने पेपर निर्माण की पूरी प्रक्रिया को नजदीक से देखा और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं।



मिल भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को विशेष रूप से वेस्ट पेपर एवं रद्दी कागज की रीसाइक्लिंग प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी अवलोकन कराया गया, जहां पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया समझाई गई। इस शैक्षणिक भ्रमण से बच्चों में पर्यावरण संरक्षण एवं संसाधनों के पुनः उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ी।

एक्सपोजर विजिट में बच्चों के साथ कुलदीप जैन, पूनम (नोडल संकुल), एआरपी राखी चौधरी, अजय शर्मा, धर्मवीर, अजीत, नवनीत कुमार (लिपिक), ऋतु जैन, नेहा, पारुल, शिप्रा, राजीव वर्मा, नीतू, हरिप्रकाश, पवन शर्मा, प्रिया रावत, मोनिका, अंशू, गोपाल शर्मा, रविन्द्र, कामिनी, कामेश्वर, कुणाल, अनिकेत, जयवंदर सहित अनेक शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

## मां चंडी जी की पालकी यात्रा का शहर में भव्य स्वागत, भक्तिमय माहौल में झूमें श्रद्धालु



**हापुड़ (शिखर समाचार)।** मंगलवार को शहर में मां चंडी जी की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई, जिसका श्रद्धालुओं ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। यह यात्रा श्री चंडी धाम से प्रारंभ होकर अशरफ बाजार, माता मोहल्ला, बुर्ज मोहल्ला सहित विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः श्री चंडी धाम पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान भक्तों में जबरजस्त उत्साह देखने को मिला। मां चंडी महारानी के जयकारों से पूरा वातावरण गूँज उठा, वहीं भजनों की धुन पर श्रद्धालु झूमते और नृत्य करते नजर आए। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पालकी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया, जिससे पूरे शहर में धार्मिक उल्लास और भक्ति का माहौल बना रहा। इस अवसर पर पालकी सेवा समिति के संस्थापक रविंद्र जितल के साथ विनय प्रकाश गुप्ता, नवीन आनंद, राहुल कंसल, मनु गर्ग, कुश शर्मा, अखिल अग्रवाल, अनुज सिंहल, दीपेश शर्मा, महेश टिहल, दीपेश वर्स, सचिन वर्मा, अंकित कोशिक, अकाश जितल, वासु गौयल, हनु गौयल, विराग गौयल, विराग गुप्ता, अनुराग शर्मा, संदीप सिंहल, नमन गौयल, दीपशु जैन, हिमांशु जैन सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।

# '2017 में निवेश पर ठहाके मारकर हंसते थे लोग'

योगी बोले: आज माफिया मुक्त प्रदेश, दुस्साहस किया तो यमराज का टिकट पक्का

लखनऊ (एजेंसी)। लोकभवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'निवेश मित्र 3.0' पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान सीएम ने कानून-व्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा- 2017 में जब हम निवेश की बात करते थे तो निवेशक ठहाके लगाकर हंसते थे। कुछ लोग कहते थे कि हमने 5 साल पहले ही संकल्प ले लिया है कि यूपी नहीं जाएंगे। सीएम ने कहा कि पहले माफिया का प्रभाव था और कोई सुरक्षित नहीं था। हर जिले में समानांतर सरकार चलती थी। कोई सुरक्षित नहीं था। तब माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई। अब माफिया कोई भी हो, दुस्साहस किया तो वह यमराज के यहाँ का टिकट काट रहा है। इसके साथ हायलैंग-एंड-प्लेड औद्योगिक शेड्स और बिजनेस पार्क स्कीम भी शुरू की गई। यह एआई आधारित सिगल विंडो पोर्टल है। इसका लक्ष्य प्रदेश को 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है। एक प्लेटफॉर्म पर 200 सेवाएं निवेश मित्र 3.0 को पूरी तरह अपडेट किया गया है। अब इस पोर्टल पर 40 से ज्यादा विभागों की करीब 200 सेवाएं मिलेंगी। पहले सेवाएं ज्यादा थीं, लेकिन अब उन्हें व्यवस्थित किया गया है। इससे प्रक्रिया आसान और तेज हो गई है। एआई चैटबॉट और रियल-टाइम अपडेट पोर्टल में एआई चैटबॉट जोड़ा गया है। यह निवेशकों की समस्याओं का तुरंत जवाब देगा। आवेदन की स्थिति पर रियल-टाइम एसएमएस अलर्ट मिलेगा। इससे हर चरण की जानकारी मिलती रहेगी। जीआईएस आधारित लैंड बैंक भी जोड़ा गया है। इससे जमीन ढूंढना आसान होगा। कम दस्तावेज, तेज



मंजूरी आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। फॉर्म में 25% कम फील्ड रखी गई हैं। दस्तावेज 15% कम किए गए हैं। प्रक्रिया के चरण जल्दी मिलेंगे। 85 कंपनियों को फायदा, 2781 करोड़ की सब्सिडी कार्यक्रम में 85 कंपनियों को प्रमाण पत्र और जमीन आवंटन दिए गए। कुल 2,781.12 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई। निवेश मैनुयैल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो रहा है। प्लग-एंड-प्ले से तुरंत शुरू होगा काम नई योजना के तहत तैयार इंडस्ट्रियल शेड्स मिलेंगे। निवेशक बिना देरी के उत्पादन शुरू कर सकेंगे। यह योजना पीपीपी मॉडल पर आधारित है। सीएम ने कहा- यूपी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में खूब उतरने के लिए टीम यूपी ने लगातार परिश्रम किया है। सीएम ने कहा- उत्तरप्रदेश को भारत का फूड बास्केट कहा जाता है। बीच के

सपने को जमीनी धरातल पर हकीकत में उतार रही है। आपने प्रदेश की डबल इंजन वाली सरकार पर विश्वास किया। उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए सरकार ने जरूरी वातावरण तैयार किया। इसे प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारकर प्रस्तुत किया गया है। आज पूरे देश में किसी भी उद्यमी के लिए निवेश का सबसे पसंदीदा स्थल उत्तरप्रदेश है। यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस विश्वास को पिछली सरकारों ने तोड़ा था। उत्तरप्रदेश वासियों और नौजवानों के सपनों को तोड़ा गया था। देश के सबसे बड़े राज्य के सामने वजूद का संकेत खड़ा किया गया था। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि डबल इंजन सरकार पर आपका जो विश्वास है, उस पर खरा उतरने के लिए टीम यूपी ने लगातार परिश्रम किया है। सीएम ने कहा- उत्तरप्रदेश को भारत का फूड बास्केट कहा जाता है। बीच के

काजर कहते थे, यूपी आइए, निवेश करिए, तो जवाब मिलाता था यूपी? कुछ लोग चुप हो जाते थे। कुछ लोग साफ कहते थे कि हमने 5 साल पहले ही तय कर लिया था कि यूपी नहीं जाएंगे। फिर भी कहते थे कि आप आए हैं, तो एक बार प्रयास करेंगे। सीएम बोले- इतना कहकर ही बातचीत खत्म हो जाती थी। यह 2017 की सच्चाई थी, जिसे हमने खुरफेस किया था। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि- पहचान का संकेत किसने खड़ा किया था? हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में समानांतर सरकार चलाने वाले माफिया गिरोहों ने खड़ा किया था। वह किसी न किसी राजनेता के गुर्गों के रूप में समानांतर सरकार चलाता था। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रहने देता था। न व्यापारी को, न बेटी को, न सामान्य नागरिक को। तब हमने तय किया कि इस माफिया की कमर तोड़नी है।

## ढाई एयरपोर्ट से 16 तक पहुंचा यूपी

सीएम ने कहा: यूपी में कभी लगभग ढाई एयरपोर्ट ही संचालित होते थे। ढाई का मतलब दो एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। जबकि गोरखपुर और आगरा आधे माने जाते थे। गोरखपुर में एक फ्लाइट आती थी, वो भी कभी-कभी। आगरा में भी यही स्थिति थी। कोई मजबूत एयर कनेक्टिविटी का वातावरण नहीं था। आज यूपी के पास 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। इसका उद्घाटन 28 तारीख को प्रधानमंत्री के कर कर्मलों से होगा। यह देश का सबसे बड़ा कार्गो और लॉजिस्टिक हब बनेगा। इसके साथ ही जेवर में एमआरओ सुविधा भी दी जा रही है। एयरक्राफ्ट मेंटेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग की यह सुविधा देश में पहली बार होगी।

कालखंड में किसान पलायन को मजबूर हुए। कई किसान आत्महत्या तक करने लगे। स्थितियां बेहद खराब थीं। लेकिन पिछले 9 वर्षों में इस सेक्टर को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया गया। परिणाम यह है कि भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का 11% यूपी के पास है। जबकि खाद्यान्न उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी 21% है। यानी 11% जमीन पर 21% उत्पादन। इसी के साथ उत्तरप्रदेश ने खुद को फिर से फूड बास्केट के रूप में स्थापित किया है। यूपी को इंडस्ट्रियल निवेश का बेहतरीन गंतव्य बनाने के लिए पिछले 9 वर्षों में कई प्रयास किए गए। उन्होंने 2017 का अनुभव शेयर किया। सीएम ने कहा- जब हम निवेश की बात करते थे, तो लोग शिष्टाचार में मिलने आ जाते थे। लेकिन जब हम प्रदेश के बाहर

जाकर कहते थे, यूपी आइए, निवेश करिए, तो जवाब मिलाता था यूपी? कुछ लोग चुप हो जाते थे। कुछ लोग साफ कहते थे कि हमने 5 साल पहले ही तय कर लिया था कि यूपी नहीं जाएंगे। फिर भी कहते थे कि आप आए हैं, तो एक बार प्रयास करेंगे। सीएम बोले- इतना कहकर ही बातचीत खत्म हो जाती थी। यह 2017 की सच्चाई थी, जिसे हमने खुरफेस किया था। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि- पहचान का संकेत किसने खड़ा किया था? हर थाना क्षेत्र में, हर जनपद में समानांतर सरकार चलाने वाले माफिया गिरोहों ने खड़ा किया था। वह किसी न किसी राजनेता के गुर्गों के रूप में समानांतर सरकार चलाता था। किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रहने देता था। न व्यापारी को, न बेटी को, न सामान्य नागरिक को। तब हमने तय किया कि इस माफिया की कमर तोड़नी है।

## संक्षिप्त डायरी

बांके बिहारी मंदिर: ठाकुरजी के दर्शन से पहले भीड़ के दबाव में चीख पड़े बच्चे-महिलाएं, ट्रैफिक व्यवस्था हुई फेल



मथुरा (एजेंसी)। श्री बांकेबिहारी मंदिर में एक बार फिर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिर परिसर में पहुंचने लगा, जो दोपहर तक बेकाबू हालात में दिखा। मंदिर के बाहर की गलियों और बाजारों में भी पैर रखने तक की जगह नहीं बची। दुकानों के सामने और मार्गों पर भक्तों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे पूरे क्षेत्र में जाम जैसे हालात बन गए। भीड़ के बीच सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों और बुजुर्ग महिलाओं को झेलनी पड़ी। कई जगहों पर धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई, जिससे लोग घबराए नजर आए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भीड़ के दबाव में कई श्रद्धालु एक-दूसरे से बिछड़ गए और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तैनात पुलिस बल के हाथ-पांव फूल गए। पुलिस द्वारा बनाए गए बैरिकेट और मार्ग नियंत्रण व्यवस्था भी भीड़ के आगे अक्षर साबित हुईं। हालात संभालने के लिए श्रद्धालुओं को रोक-रोककर भेजा गया, लेकिन संख्या इतनी अधिक थी कि व्यवस्था लगातार टूटती नजर आई। निर्धारित स्थानों पर श्रद्धालुओं को रोकने की योजना सफल नहीं हो सकी और भीड़ सीधे मंदिर की ओर बढ़ती रही।

पश्चिम एशिया युद्ध से दुनिया को नुकसान, मोहन भागवत की बड़ी चेतावनी, वृंदावन से दिया ये संदेश



वृंदावन (एजेंसी)। रुक्मिणी विहार में स्थित नव-निर्मित जीवनदीप आश्रम का भव्य लोकार्पण संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया। इस सर पर स्वामी यतिदानंद महाराज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी सहित कई गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित रहे। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि जीवन में आने वाले उतार-चढ़ावों और कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि 'जीवन के थपेड़ों से लड़ना है, हारना नहीं।' आश्रमों को धर्म की शिक्षा का केंद्र बनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये स्थान न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि भौतिक शरीर को ऊर्जावान, ओजस्वी और तेजस्वी बनाने में भी सहायक होते हैं। मोहन भागवत ने विश्व में व्याप्त तनाव और कलह पर चिंता व्यक्त की। विशेष रूप से पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कलह से केवल नुकसान ही हो रहा है। उन्होंने बदले की भावना से किए जा रहे कार्यों को गलत ठहराया और शांति व सौहार्द का संदेश दिया। संघ प्रमुख ने धर्मांतरण को रोकने में समाज की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्य केवल कानून का ही नहीं, बल्कि समाज का भी है। उन्होंने घुसपैठियों को रोकने और बिना अनुमति देश में आकर रोजगार प्राप्त करने वाले विदेशियों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता पर बल दिया।

बदायूं को बड़ी सौगात: अब दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा, रेलवे ने इस ट्रेन के विस्तार को दी हरी झंडी



बदायूं (एजेंसी)। लंबे समय से रेल सुविधा की मांग कर रहे बदायूं के लोगों के लिए आश्चर्यकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने बरेली-नई दिल्ली एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 14315/14316) का विस्तार बदायूं होते हुए कासगंज रेलवे स्टेशन तक करने की मंजूरी दे दी है। अब जिले के हजारों यात्रियों को सीधे राजधानी दिल्ली तक आवागमन की सुविधा मिल सकेगी, जिससे यात्रा और भी सुगम हो जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में इस बात की पुष्टि की गई है। यह स्वीकृति केंद्रीय राज्य मंत्री पी.एल. वर्मा द्वारा 20 नवंबर 2025 को भेजे गए पत्र के संदर्भ में प्रदान की गई है। रेल मंत्रालय के इस निर्णय को क्षेत्रीय विकास और जनसुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि बदायूं सहित आसपास के जिलों के लोगों को अब दिल्ली जाने के लिए अतिरिक्त ट्रेनों या बार-बार साधन बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह ट्रेन सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे यात्रियों का समय बचेगा और यात्रा अधिक आरामदायक होगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा व्यापार, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगी। गौरतलब है कि इस मांग को लेकर बदायूं के सांसद आदित्य यादव ने भी लोकसभा में मुद्दा उठाया था। अब इसे मंजूरी मिल गई है। स्थानीय स्तर पर इस निर्णय को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। रेल मंत्री के जारी पत्र के अनुसार, इस ट्रेन के विस्तार से बदायूं, कासगंज और बरेली मंडल के बीच आवागमन को नई गति मिलेगी। यह ट्रेन न केवल दैनिक यात्रियों बल्कि प्रतिगोष्ठी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों के लिए भी बेहद लाभकारी साबित होगी। लोग का मानना है कि रेल सेवाओं के विस्तार से क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। बदायूं जैसे जिलों में बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी और स्थानीय बाजारों को नई पहचान मिलेगी। साथ ही पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने का उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर, बरेली-नई दिल्ली एक्सप्रेस का कासगंज तक विस्तार बदायूं जनपद के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।

## दुकान पर हमला: मां बेटे समेत परिवार पर लाठी डंडों से हमला, 12 अज्ञात पर केस दर्ज

दादरी (शिखर समाचार)।

कोतवाली दादरी क्षेत्र के रायपुर बांगर गांव में दुकान पर बेटे मां बेटे और उनके परिवार पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आरोपियों ने लाठी डंडों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़िता सरोज ने बताया कि 20 मार्च को शाम वह अपने बेटे प्रेमचंद के साथ दुकान पर बैठी थीं, तभी दो युवक आए और विवाद शुरू कर दिया। विरोध करने पर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर अन्य परिजन पहुंचे तो करीब 12 लोग मौके पर आए और सभी पर हमला कर दिया। घायलों को ग्रेटर नोएडा के अस्पताल



में भर्ती कराया गया है। सरोज की शिकायत पर पुलिस ने 12 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

## एक्सप्रेस ट्रेन में हंगामा: चैन पुलिंग और अवैध वेंडिंग करते दो आरोपी गिरफ्तार

दादरी (शिखर समाचार)।

दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्सप्रेस ट्रेन में अवैध गतिविधियों में लिप्त दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी ट्रेन में बिना अनुमति खाद्य सामग्री बेच रहा था, जबकि दूसरा चैन पुलिंग कर भागने की कोशिश में पकड़ा गया।

आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार के अनुसार 23 मार्च की शाम मगध एक्सप्रेस दिल्ली की ओर जा रही थी। सिकंदरपुर और चोला स्टेशन के बीच एस 1 कोच में जांच



के दौरान हाथरस जनपद के महमूदपुर निवासी श्यामू को अवैध खाद्य सामग्री बेचते हुए पकड़ा गया। वहीं, अलीगढ़ के कैलाश नगर निवासी रवि कुमार को आवागमन

दादरी रेलवे स्टेशन के बीच चैन पुलिंग कर उतरते समय गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

## पति ने पत्नी और उसके आशिक को उतारा गोली मार के मौत के घाट, तलाश में जुटी पुलिस

गाजियाबाद (शिखर समाचार)।

थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में उसे समय अफरा तफरी का माहौल मच गया, जब लोगों ने एक के बाद एक गोली चलाने की आवाज सुनी। गोली की आवाज सुनते ही लोगों की भीड़ मौके पर लग गई और गोली मारने वाला पति राशिद भीड़ के सामने से ही निकल कर फरार हो गया। गोली चलाने की सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की। पुलिस ने मौके पर देखा कि एक महिला शबनम और एक पुरुष फहीम मृत अवस्था में मौजूद हैं। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच शुरू की। वहीं परिजनों की शिकायत पर थाना ट्रॉनिका सिटी पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी राशिद की तलाश इस समय पुलिस कर रही है। पूरा मामला थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के राम पार्क इलाके के बुध बाजार मोहल्ले का है। जहां पर राशिद अपने परिवार के साथ रहता था। राशिद के साथ बच्चे हैं, जिसमें से बड़े बेटे का निकाह कुछ दिन पूर्व भी हुआ था। राशिद सेनेटरी का काम किया करता था और फहीम उसके साथ



मृतका - शबनम



मृतक - फहीम

रहकर काम किया करता था। फहीम के राशिद की बीवी शबनम के साथ संबंध बन गए थे। राशिद ने इसका विरोध करते हुए दोनों को कई बड़ी समझाया था। राशिद के बड़े बेटे को इस बारे में पूरी जानकारी थी और उसका निकाह होने के बाद इस बात का ज्यादा विरोध होने लगा था। राशिद अपने घर पहुंचा और शबनम व फहीम के साथ खाना खाने लगा। दोनों के बीच के संबंध का गुस्सा निकालते हुए उसमें एक-एक करके दोनों को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि डायल 112 पर सूचना आई थी कि थाना

ट्रॉनिका सिटी अंतर्गत बुद्ध बाजार नामक मोहल्ले में एक झगड़ा हुआ है, जिसमें दो लोग घायल हुए हैं। इस सूचना पर थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस मौके पर पहुंची, तो राशिद नामक व्यक्ति के मकान में शबनम नामक महिला जिसकी उम्र लगभग 36 वर्ष है और फहीम नामक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है का शव पड़ा हुआ था। शबनम राशिद का दोस्त बताया गया और यह भी बताया गया कि फहीम और शबनम के संबंध थे, जिसका राशिद द्वारा विरोध किया जाता था। पूछताछ से यह भी पता चला है कि राशिद द्वारा

## हापुड़ में गैस लाइन में लगे युवक को आया हार्टअटैक

उन्नाव में हाईवे जाम किया, कानपुर में महिला बोली- मर जाऊंगी तो बच्चों का क्या होगा

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में गैस सिलेंडर की किल्लत जारी है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। मंगलवार सुबह 11 बजे हापुड़ में गैस एजेंसी पर सिलेंडर के लिए लाइन में लगे 35 साल के युवक को हार्ट अटैक आ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने उसे CPR देने की कोशिश की, फिर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। युवक पप्पू कविनगर का रहने वाला है और कार चलाता है। सिलेंडर की लाइन में हार्ट अटैक का यह देश में तीसरा मामला है। इससे पहले फर्रुखाबाद में मुखर अहरी (75) और पंजाब के बरनाला जिले में भूपण कुमार मित्तल (66) को हार्ट अटैक आ गया था। दोनों की जान चली गई थी। इधर, उन्नाव में भैयाजी गैस एजेंसी को बिना सूचना बंद किए जाने से लोग नाराज हो गए। दोपहर 1 बजे लोगों ने कानपुर-लखनऊ हाईवे पर सिलेंडर रखकर जाम लगा दिया। बाद में पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। वहीं, कानपुर में सिलेंडर लेने एजेंसी पर पहुंचे लोगों ने कहा कि OTP आने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। गैस एजेंसी पहुंचने पर कहा जाता



है कि आपको बुकिंग नहीं है। 55 साल की महिला मुमताज ने कहा- मेरे घर में 5 बेटियां हैं। पच्ची मिलने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा। एजेंसी वाले रोज दौड़ा रहे हैं। मुझे इड की बीमारी है। रोज 200 रुपए आने-जाने में लग रहे हैं। हम घर जाएंगे तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। प्रदेश में गैस सिलेंडर को लेकर 15 दिन से परेशानी बनी हुई है। अफसरों का दावा है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। लोग पैकिंग को रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। कानपुर की माल रोड स्थित सुमिता गैस एजेंसी पर सुबह 8 बजे से ही लोग पहुंचने लगे। यहां सिलेंडर लेने एजेंसी पर पहुंचे कराने के लिए लोगों की भीड़ रही। लोगों ने बताया कि एजेंसी आमतौर पर सुबह 10:30 बजे

खुल जाती है, लेकिन अब 11 बजे तक भी नहीं खुल रही है। मोतीलाल ने कहा- मैंने 11 मार्च को गैस बुक की थी। आज तीसरी बार आया हूँ, लेकिन घर बांका कहा जाता है कि गाड़ी नहीं आई है और सिलेंडर घर पर भेजा जाएगा। आज जब मैं यहां पहुंचा, तो गैस एजेंसी खुली ही नहीं थी। कानपुर में 55 साल की महिला मुमताज ने कहा- मेरे घर में 5 बेटियां हैं। पच्ची मिलने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। एजेंसी वाले रोज दौड़ा रहे हैं। मुझे बीपी की बीमारी है। रोज 200 रुपए आने जाने के लग रहे हैं। हम घर जाएंगे तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। उन्नाव में भैयाजी गैस एजेंसी को बिना सूचना बंद किए जाने से लोग नाराज हो गए। उन्होंने कानपुरझलखनऊ हाईवे



पर सिलेंडर रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर जाम खुलवाया और यातायात बहाल करायी। हापुड़ के कविनगर में भारत गैस एजेंसी पर सिलेंडर के लिए लाइन में लगे 35 साल के युवक को हार्ट अटैक आ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने उसे उद्घेदन की कोशिश की, फिर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। युवक पप्पू कविनगर का रहने वाला है और कार चलाता है। कानपुर के सुरेश तिवारी ने कहा- मैं गैस के लिए पिछले एक हफ्ते से परेशान हूँ। एजेंसी और कंट्रोल रूम में फोन कर रहा हूँ, लेकिन समस्या का निस्तार नहीं हो पा रहा है। पिछले कई दिनों से घंटों लाइन में लगने के बाद एजेंसी संचालक मुझे कल आने

की बात कहकर लौटा देते हैं। यहां कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और गैस को लेकर मैं काफी समय से परेशान हूँ। जबकि डीएम और अधिकारी यह आश्वासन दे रहे हैं कि शहर में गैस को लेकर कोई संकट नहीं है। गैस न होने की वजह से हाल यह है कि बच्चों को चार दिन से खाना नहीं मिल पा रहा है। कानपुर के शिवराज गुप्ता ने बताया- गैस को लेकर शहर में काफी ज्यादा संकट है। कई जगह गैस की कालाबाजारी भी हो रही है। अगर अधिकारी एक बार सड़क पर उतरकर एजेंसियों के चक्कर लगाएँ, तो उन्हें खुद पता चल जाएगा कि किस तरह लोग गैस की दिक्कत से परेशान हैं। कागजी और जमीनी हकीकत में काफी अंतर है। जब एजेंसी स्तर पर ही

समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो कंट्रोल रूम से समाधान कैसे होगा। पिछले चार दिन से मैं खुद यहां आकर घंटों लाइन में लग रहा हूँ, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। शहर में गैस को लेकर गंभीर संकट है। अधिकारी लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कानपुर में रोहित पांडेय ने कहा- मैंने 8 मार्च को सिलेंडर बुक किया था, लेकिन अभी तक गैस की डिलीवरी नहीं हो सकी है। जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है, उसी को गैस की डिलीवरी मिल रही है। जबकि मैं पिछले 48 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। फोन करने पर काल नहीं उठाई जाती और जब एजेंसी पर पहुंचता हूँ तो उल्टा-सीधा जवाब देकर भेज दिया जाता है। करीब एक हफ्ते से गैस को लेकर एजेंसी के चक्कर काट रहा हूँ। आज भी सुबह करीब 3 घंटे से लाइन में लगा हुआ हूँ। जब कंट्रोल रूम में शिकायत की गई तो कहा गया कि आज या कल में सिलेंडर आ जाएगा, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है। अब तो हाल यह है कि कंट्रोल रूम में भी फोन उठाना बंद कर दिया गया है। कानपुर के कल्याणपुर में संसार गैस एजेंसी के बाहर सिलेंडर के लिए लोगों की लाइन लगी है। लोग सुबह से ही घुप में सिलेंडर के लिए खड़े हैं।

# विश्व टीबी दिवस 2026 पर बड़ी पहल: 100 दिन में टीबी मुक्त भारत का संकल्प, घर घर पहुंचेगी जांच और इलाज

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। विश्व क्षय रोग दिवस 2026 के अवसर पर गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान टीबी मुक्त भारत ऐप (खुशी 100 निश्चय मित्र), टीबी फ्री अर्बन वाई इनिशिएटिव का उद्घाटन किया गया तथा निःशुल्क जांच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो टीबी मरीजों तक घर घर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री वृजेश पाठक सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।



मंत्री ने कहा कि भारत सरकार 2026 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि 100 दिन का यह अभियान जनभागीदारी, तकनीकी नवाचार और सामुदायिक सहयोग के जरिए टीबी के खिलाफ लड़ाई को तेज करेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे

इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं और जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने बताया कि अब आधुनिक तकनीकों के जरिए टीबी की जांच अधिक सटीक और तेज हो रही है। साथ ही पोषण अभियान के माध्यम से मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार लाने पर भी विशेष



ध्यान दिया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री वृजेश पाठक ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 7 दिसंबर 2024 से 9 मार्च 2026 तक 3.28 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। राज्य में एनएटी मरीजों की संख्या 141 से बढ़कर 1004 कर दी गई है और करीब 64 प्रतिशत जांच अब

इसी तकनीक से हो रही है। इसके अलावा एआई आधारित 87 से अधिक हैंड हेल्ड एक्सरे मशीनों के जरिए दूरदराज क्षेत्रों में भी जांच संभव हो पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ड्रग सेंसिटिव टीबी के उपचार की सफलता दर 92 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया

पटेल ने कहा कि टीबी के खिलाफ लड़ाई केवल स्वास्थ्य क्षेत्र तक सीमित नहीं, बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत बड़े स्तर पर घर घर स्क्रीनिंग, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स के जरिए जांच और समय पर उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। खासतौर पर संवेदनशील और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्यक्रम में लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों और टीबी उन्मूलन से जुड़े स्टॉल्स का अवलोकन किया गया। इस दौरान टीबी विजेताओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने जागरूकता फैलाकर समाज में बदलाव लाने का कार्य किया।

मिशन शक्ति के तहत छात्रा बनी एक दिन की जिला विद्यालय निरीक्षक, प्रशासनिक कार्यों का लिया अनुभव



शामली (शिखर समाचार)। जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत छात्राओं को सशक्त बनाने और उनमें आत्मविश्वास विकसित करने के उद्देश्य से एक दिन का अधिकारी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल के तहत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की कक्षा 11 की छात्रा एकता जागिड़ को एक दिन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) बनाया गया। कार्यक्रम के दौरान एकता जागिड़ ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचकर वृद्ध के कार्यों को नजदीक से समझा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद करते हुए शिक्षा विभाग के कामकाज, कार्यालय प्रणाली तथा शिवायत निस्तारण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को समझते हुए विभिन्न अभिलेखों और व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। जिला विद्यालय निरीक्षक ऐश्वर्या जायसवाल ने छात्रा को विभागीय प्रक्रियाओं से अवगत कराया और कार्यालय का निरीक्षण भी करवाया। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत छात्राओं को प्रशासनिक कार्यों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर छात्रा एकता जागिड़ के पिता प्रमोद जागिड़ उर्फ राजू मेखर, विद्यालय के प्रधानाचार्य रविन्द्र कुमार तथा लिपिक धर्मद कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं में प्रशासनिक सेवाओं के प्रति रुचि बढ़ाने और उनके व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहित करने का संदेश भी दिया गया।

पॉलिथीन के गोदाम पर नगर निगम टीम ने मारा छापा, 2 लाख का वसूला जुमाना



गाजियाबाद (शिखर समाचार)। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश अनुसार लगातार शहर में जन-जन को प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करने, प्रतिबंधित प्लास्टिक का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। इसके अलावा गाजियाबाद नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम पॉलिथीन के गोदाम बंद करने के लिए भी कार्यवाही कर रही है। मोहन नगर जौन के साहिबाबाद क्षेत्र में सफाई एवं खाद्य निरीक्षण संजिव के द्वारा कार्यवाही कराई गई तथा पॉलिथीन के गोदाम से लगभग 27473 किलो पॉलिथीन जम की गई और 2 लाख का जुमाना भी वसूला गया। मौके पर जौनल प्रभारी एसपी सिंह, तथा चीफ सेनेटेरी ऑफिसर विनोद भी उपस्थित रहे। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश ने बताया कि गाजियाबाद नगर निगम लगातार प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है। साहिबाबाद क्षेत्र के मरस हरियाणा गोड्डन टॉसपोर्ट गोदाम पर पहुंचकर निगम स्वास्थ्य विभाग टीम ने कार्यवाही की। पॉलिथीन जम करते हुए मौके पर पॉलिथीन को कांटे पर तलवाया गया और 2 लाख का जुमाना भी वसूला गया है। भविष्य में इस प्रकार का कृत्य ना हो संबंधित को चेतावनी भी दी गई। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में भी लगातार प्रतिबंधित प्लास्टिक की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए शहर वासियों से अपील की जा रही है। प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। अभियान के दौरान मौके पर पुलिस का भी विशेष सहयोग निगम को मिला। परवर्तन दल की टीम मौके पर बनी रही और प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलिथीन के 1000 बैग को जब्त किया गया।

महिला कोच में घुसना पड़ा भारी: दो यात्री गिरफ्तार, आरपीएफ की सखी से मचा हड़कंप

दादरी (शिखर समाचार)। दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर महिला कोच में अवैध रूप से यात्रा करने वाले दो यात्रियों के खिलाफ आरपीएफ ने कार्रवाई की है। दोनों को पकड़कर रेलवे अधिष्ठाता के तहत मामला दर्ज किया गया। आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि अलीगढ़ से दिल्ली जा रही 64152 लोकल पैसंजर ट्रेन दादरी स्टेशन पर रुकी थी। इसी दौरान महिला कोच में जांच के दौरान दो पुरुष यात्री अवैध रूप से यात्रा करते पाए गए। दोनों को ट्रेन से उतारकर आरपीएफ कोतवाली ले जाया गया, जहां उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। बाद में उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद महिला कोच में अवैध यात्रा करने वालों में हड़कंप मच गया है।

अधिवक्ता पर जानलेवा हमला: रास्ते में घेरकर लाठी डंडों से पीटा, चार आरोपी नामजद

दादरी (शिखर समाचार)। जारवा कोतवाली क्षेत्र के छैलस गांव में एक अधिवक्ता पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि चार लोगों ने रास्ते में रोककर लाठी डंडों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस के अनुसार अधिवक्ता फराज हेर 21 मार्च की रात अपने पक्षकार से मिलकर लौट रहे थे। इसी दौरान रिजवान, मुर्तजा, आसिफ और जफर ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने हमला करने शुरू किया। घायल अधिवक्ता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद उन्होंने चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

## जेवर एयरपोर्ट लोकार्पण की तैयारियां तेज : जिलाधिकारी का ग्राउंड निरीक्षण, व्यवस्थाओं को लेकर सख्त निर्देश

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर पर प्रस्तावित लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मंच व्यवस्था, रैली स्थल, पार्किंग, आमजन, वीआईपी व वीवीआईपी आवागमन, सुरक्षा प्रबंधन और यातायात व्यवस्था का गहन अवलोकन किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों और आम नागरिकों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर



दिया। साथ ही पार्किंग स्थलों, एंटी-एग्जेंट प्लांट्स और प्रमुख मार्गों पर उचित साइनेज, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन सुनिश्चित करें, ताकि लोकार्पण कार्यक्रम सफल,

सुव्यवस्थित और गरिमामय तरीके से संपन्न हो सके। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, उप जिलाधिकारी जेवर दुर्गा सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कंचन सहित जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

## जनसमस्याओं को लेकर जाट महासभा ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, समाधान की उठाई मांग

शामली (शिखर समाचार)। अखिल भारतीय जाट महासभा के युवा जिलाध्यक्ष मुकुल चौधरी के नेतृत्व में जनपद की विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में आम जनता और किसानों से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर की भारी किल्लत बनी हुई है, जिसके चलते कालाबाजारी खुलेआम हो रही है। आम उपभोक्ताओं को मजबूरी में अधिक कीमत पर गैस सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसके साथ ही किसानों को डीएपी और एनपीके खाद समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे खेती का कार्य प्रभावित हो रहा है। यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी फसल उत्पादन पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।



इसके अतिरिक्त आवारा पशुओं की समस्या को भी गंभीर बताते हुए कहा गया कि ये पशु किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की गई है। ज्ञापन में जनपद के बाईपास मार्गों पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर भी चिंता जताई गई। आए दिन हो रहे हादसों में जनहानि की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको देखते हुए संबंधित मार्गों पर स्पीड ब्रेकर, स्ट्रीट लाइट तथा पुलिस निगरानी को

समूचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की गई है। वहीं, जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया। हाल ही में एक जनप्रतिनिधि को मिली धमकी को गंभीर बताते हुए कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की गई। इस दौरान मुकुल चौधरी, पप्पू लपराना, विरेन्द्र, परमवीर, बहादुर, अमजद खान, अरविन्द खोडसामा, विनय कुमार, हर्ष, सोराम प्रधान सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

## नन्ही छात्रा दिविषा सिंह को डीएम ने किया सम्मानित, स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजी गई



हापड़ (शिखर समाचार)। माउंट कालम्बस इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिकोत्सव के अवसर पर नन्ही छात्रा दिविषा सिंह को जिलाधिकारी अभिषेक पाण्डेय द्वारा स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि से विद्यालय और क्षेत्र में हर्ष का माहौल है तथा लोगों ने दिविषा को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। नगर के श्रीनगर निवासी राजीव तोमर (दरोगा) की नातिन तथा रूपेंद्र और पूरवीता की पुत्री दिविषा सिंह ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन, अनुशासन और प्रतिभा के बल पर यह सम्मान प्राप्त किया। वार्षिकोत्सव समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बड़े चढ़कर भाग लिया। समारोह के दौरान जिलाधिकारी अभिषेक पाण्डेय ने दिविषा सिंह की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतिभा अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। उन्होंने छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों को अपनाने और जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा सहित विद्यालय प्रबंधन एवं अन्य गणमान्य लोगों ने भी दिविषा सिंह को बधाई देते हुए उसके उज्वल भविष्य को कामना की।

## विश्व क्षय रोग दिवस पर शामली की 9 ग्राम पंचायतों टीबी मुक्त घोषित, सम्मान समारोह में मिला सम्मान

शामली (शिखर समाचार)। विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर नवीन कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में जनपद की 9 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीरेन्द्र सिंह, रामजी लाल कश्यप तथा सत्येन्द्र सिंह ने संयुक्त रूप से की। इस अवसर पर जनपद को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई और संबंधित विभागों एवं सामाजिक संस्थाओं के योगदान को महत्वपूर्ण बताया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा टीबी मरीजों को गोद लेकर उनके लिए पोषण पोर्टली किट वितरित की गई। यह पहल मरीजों के पोषण स्तर को सुधारने और उपचार को प्रभावी बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम मानी जा रही है। मुख्य अतिथि वीरेन्द्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि टीबी जैसी बीमारी को समाप्त करने के लिए जनजागरूकता, संतुलित आहार और समय पर जांच अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इस अभियान से जुड़कर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जिलाध्यक्ष रामजी



लाल कश्यप ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य तभी संभव है जब आमजन, जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग मिलकर कार्य करें। उन्होंने सभी से अपील की कि टीबी के प्रति किसी भी प्रकार की भ्रांतियों को दूर करें और मरीजों को सामाजिक सहयोग प्रदान करें। प्रभारी जिलाधिकारी सत्येन्द्र सिंह ने कहा कि टीबी का इलाज पूरी तरह निशुल्क है और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का लाभ उठाकर इस बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया

कि चयनित ग्राम पंचायतों को महात्मा गांधी की प्रतिभा एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि हरमजपुर को स्वर्ण श्रेणी, रसूलपुर, यापुर और हिंगोखेड़ी को रजत श्रेणी में सम्मानित किया गया, जबकि अन्य ग्राम पंचायतों को कांस्य श्रेणी प्रदान की गई। यह उपलब्धि जनपद के लिए गौरव का विषय है और अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ विनोद कुमार ने बताया कि वर्तमान में जनपद में 2701 टीबी मरीजों का उपचार चल रहा है, जिन्हें सरकार द्वारा निशुल्क दवा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही निश्चय पोषण योजना के अंतर्गत मरीजों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है, जिससे उनके पोषण स्तर में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि नियमित दवा सेवन और चिकित्सकीय परामर्श का पालन करने से टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। कार्यक्रम के अंत में टीबी उन्मूलन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने जनपद में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसे समाप्त करने के संकल्प को और अधिक मजबूत करने का कार्य किया।

## जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन को लेकर तेज हुई तैयारियां, 28 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे लोकार्पण

ग्रेटर नोएडा (शिखर समाचार)। प्रस्तावित जेवर (नोएडा इंटरनेशनल) एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, राज्यमंत्री कुंवर वृजेश सिंह, प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी, प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर, परिष्कार क्षेत्रीय अध्यक्ष संदेन्द्र शिशोदिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉ. महेश शर्मा, नोएडा विधायक पंकज सिंह, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, एमएलसी श्रीचन्द्र शर्मा, एमएलसी नरेन्द्र भाटी, विधायक तेजपाल नागर सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे। इस



सफल बनाएं। प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी ने कहा कि गांव गांव प्रचार प्रसार, आमंत्रण टोली और बस प्रमुखों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है, ताकि जनसभा को ऐतिहासिक बनाया जा सके। वहीं, क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेन्द्र शिशोदिया ने कहा कि जनसभा को लेकर जनता में भारी उत्साह है और सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद डॉ. महेश शर्मा ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के

नए अवसर प्राप्त होंगे। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में यह एयरपोर्ट क्षेत्र के विकास का नया अध्याय लिखेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति भी प्रस्तावित है और क्षेत्र की जनता इसमें बड़े चढ़कर भाग लेने के लिए तैयार है। इस अवसर पर पूर्व राजसभा सांसद कांता कदम, जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा, क्षेत्रीय महामंत्री हरिश ठाकुर, मान सिंह गोस्वामी, सिखेंद्राबाद विधायक लक्ष्मीराज सिंह, विधायक मोनाक्षी सिंह, मांटे विधायक प्रदीप चौधरी, लोनी विधायक नन्द किशोर गुजर, महानगर अध्यक्ष महेश चौहान, बुलंदशहर अध्यक्ष विकास चौहान, गाजियाबाद अध्यक्ष मयंक गोयल सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

## व्यापारियों की समस्याओं पर मंथन, एकजुटता और कानून की जानकारी पर दिया जोर

शामली (शिखर समाचार)। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश की शामली इकाई को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने व्यापारियों की वर्तमान समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में व्यापारी वर्ग को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में एकजुटता के साथ साथ व्यापारिक कानूनों की सही जानकारी होना बेहद आवश्यक है। शहर के रॉक गोल्ड एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकेश अग्रवाल ने कहा कि आज व्यापारी लगभग 28 विभागों के दबाव और उत्पीड़न का सामना कर रहा है, जिससे व्यापार करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा



रहा है। उन्होंने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि बिजली विभाग को पहले अपने सर्वर सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, उसके बाद ही स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में व्यापारी की छवि एक अपराधी के रूप में प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें

लिपि नियम अधिक कठोर हैं। इससे छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा बार-बार नमूना जांच कर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, जबकि नमूना जांच के स्पष्ट मानक तय नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खेतों में पानी और कीटनाशकों के उपयोग को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं हैं, जिससे व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव बनता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल चैरमैन सुनील गोयल ने की, जबकि संवर्धन प्रदेश संयुक्त महामंत्री गौरव रहेला ने किया। इस अवसर पर अरविंद कुमार, डॉ. राजेंद्र गोयल और हिमांशु जैन सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

## संपादकीय

## सोने चांदी की फीकी पड़ी चमक: बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और भविष्य की दिशा

वैश्विक बाजारों में सोने और चांदी की चमक लंबे समय से आर्थिक अनिश्चितताओं का प्रतीक मानी जाती रही है, लेकिन 24 मार्च 2026 के परिदृश्य में इनकी पारंपरिक चमक कुछ फीकी पड़ती नजर आ रही है। यह बदलाव केवल कीमतों के उतार चढ़ाव तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश की बदलती मानसिकता और वैश्विक अर्थव्यवस्था के नए स्वरूप का संकेत भी है। आज जब दुनिया तकनीक, डिजिटल निवेश और तेज रिटर्न की ओर बढ़ रही है, तब सोने चांदी जैसे पारंपरिक विकल्पों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

पिछले कुछ समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता के संकेत मिले हैं। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरों का संतुलन, महंगाई पर नियंत्रण और निवेशकों का बढ़ता आत्मविश्वास ऐसे कारक हैं जिन्होंने जोखिम वाले क्षेत्रों की ओर पूंजी के प्रवाह को बढ़ाया है। टेकोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित ऊर्जा और डिजिटल परिवर्तन आज निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं। ऐसे में सोना और चांदी, जो परंपरागत रूप से सुरक्षित निवेश माने जाते थे, अब प्राथमिक विकल्प नहीं रह गए हैं। भारत जैसे देश में यह बदलाव और भी दिलचस्प है। यहां सोना केवल एक निवेश नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। शादियों, त्योहारों और पारिवारिक परंपराओं में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन नई पीढ़ी की सोच अलग है। आज का युवा निवेशक भावनाओं से ज्यादा आंकड़ों और रिटर्न पर ध्यान देता है। यह म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और डिजिटल निवेश को प्राथमिकता दे रहा है, जिससे सोने चांदी की मांग पर असर पड़ रहा है। इसके साथ ही डिजिटल करेंसी और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की बढ़ती स्वीकार्यता ने भी पारंपरिक निवेश विकल्पों को चुनौती दी है। जब लेन देन और निवेश का बड़ा हिस्सा डिजिटल हो रहा है, तब भौतिक संपत्तियों की उपयोगिता सीमित होती जा रही है। निवेशक अब ऐसे विकल्प चाहते हैं जो अधिक लिक्विड हों, आसानी से ट्रांसफर हो सकें और कम समय में बेहतर रिटर्न दे सकें।

हालांकि, इन सभी परिवर्तनों के बीच यह मान लेना गलत होगा कि सोने और चांदी का महत्व समाप्त हो रहा है। इतिहास यह बताता है कि जब भी वैश्विक संकट आता है चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो या प्राकृतिक तब निवेशक फिर से सुरक्षित विकल्पों की ओर लौटते हैं। सोना और चांदी ऐसे समय में भरोसे का आधार बने रहते हैं। इसलिए इनकी प्रासंगिकता पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती, बल्कि उनका स्वरूप और भूमिका बदल रही है। अब यदि भविष्य की बात करें तो सोने और चांदी का रास्ता पूरी तरह समाप्त की ओर नहीं, बल्कि पुनर्परिभाषा की ओर जाता दिखाई देता है। आने वाले वर्षों में इन धातुओं का उपयोग केवल आभूषण या पारंपरिक निवेश तक सीमित नहीं रहेगा। तकनीकी क्षेत्र में, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा में चांदी की मांग बढ़ने की संभावना है। वहीं, सोना भी वित्तीय सुरक्षा के प्रतीक के रूप में अपनी जगह बनाए रखेगा।

भविष्य में यह भी संभव है कि सोने का डिजिटल स्वरूप और अधिक लोकप्रिय हो। डिजिटल गोल्ड, गोल्ड एटीएफ और अन्य वित्तीय उत्पादों के माध्यम से लोग बिना भौतिक सोना खरीदे उसमें निवेश कर सकेंगे। इससे सोने की पहुंच और उपयोगिता दोनों बढ़ेंगी, लेकिन पारंपरिक खरीदारी की प्रवृत्ति में बदलाव आएगा। सरकारें भी सोने के आयात को नियंत्रित करने और घरेलू बचत को उत्पादक क्षेत्रों में लगाने के लिए नई नीतियां बना सकती हैं।



राज कुमार सिन्हा

ई

रान के साऊथ पार्स गैस फील्ड पर इजरायली हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है। साउथ पार्स गैस फील्ड पर यह हमला केवल एक सैन्य घटना नहीं है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा प्रहार है। आपूर्ति में रुकावट के कारण कई देशों को लंबे समय तक ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ सकता है। द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इतिहास का सबसे खराब वैश्विक ऊर्जा व्यवधान बताया है, जो 1973 के अरब तेल प्रतिबंध को भी पीछे छोड़ दिया है। मुख्य निवेश अधिकारी डैन पिकरिंग ने कहा कि आप ऊर्जा संरक्षण के जरिए इस समस्या से बच नहीं सकते। इसका नतीजा यह होगा कि कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी कि लोग उपभोग करना बंद कर देंगे। यह पहली बार है जब खाड़ी क्षेत्र में ईरान के ऊर्जा ढांचे की सीधे निशाना बनाया गया है। 17 मार्च तक, अमेरिका और इजराइल ने खाड़ी में ईरान के ऊर्जा उत्पादन केंद्रों को निशाना बनाने से परहेज किया था। यहां तक कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के 90 प्रतिशत तेल निर्यात के केंद्र खारग द्वीप पर हमला किया, तब भी केवल सैन्य टिकानों को ही निशाना बनाया गया था। इजराइल द्वारा कतर के साथ



निरज कुमार दुबे

पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में बिगड़ते हालात के चलते दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां तेल केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि सत्ता, रणनीति और अस्तित्व का सवाल बन चुका है। ताजा हालात बता रहे हैं कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने देशों को झकझोर कर रख दिया है। ऑस्ट्रेलिया में कीमतें करीब बत्तीस प्रतिशत उछलीं, पाकिस्तान में पच्चीस प्रतिशत और अमेरिका में चौबीस प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी ने साफ कर दिया है कि यह संकट केवल आर्थिक नहीं, बल्कि वैश्विक अस्थिरता का संकेत है। जर्मनी, चीन, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन से लेकर जापान तक हर देश इस आग में झुलस रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकारें अब सीधे जनता की जिंदगी में दखल दे रही हैं। पाकिस्तान में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए, चार दिन का कार्य सप्ताह लागू किया गया और सरकारी कर्मचारियों के लिए आधा काम घर से करने का आदेश जारी हुआ। गैर जरूरी सरकारी वाहनों को सड़कों से हटाया गया और ईंधन आवंटन में पचास प्रतिशत कटौती कर दी गई। यह कदम साफ दिखाता है कि संकट कितना गहरा है।

साझा किए जाने वाले साऊथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमले के बाद यह स्थिति बदल गई है। पार्स गैस फील्ड दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार का हिस्सा है, जिसे ईरान कतर के साथ साझा करता है। इस घटना को अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध को बड़े ऊर्जा संकट के रूप में देखा जा रहा है। जबकि ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और कतर के ऊर्जा टिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने सऊदी अरब में तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी के साथ-साथ कतर और यूएई में गैस सुविधाओं पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। यह युद्ध का एक खतरनाक मोड़ साबित हो रहा है। साउथ पार्स गैस क्षेत्र, भारत सहित वैश्विक एलएनजी आपूर्ति की रीढ़ है। इजरायली हमले के बाद तेल और गैस की कीमतों में आई तत्काल वृद्धि से इससे महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरान द्वारा होमुजुम जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाने के कारण दुनिया पहले से ही कच्चे तेल की आपूर्ति में व्यवधान से जूझ रही है। ऐसे में उत्पादन सुविधाओं को होने वाली किसी भी क्षति का प्रभाव वर्षों तक बना रह सकता है। होमुजुम जलडमरूमध्य में चल रही बाधाओं ने यह दिखा दिया है कि एक छोटा समुद्री मार्ग भी वैश्विक सप्लाई चेन को हिला सकता है। कतर के रास लाफान औद्योगिक शहर, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यात केंद्र है, ईरानी मिसाइल हमलों से तबाह हो गया है। रास लाफान पर हमलों के कारण कतर की कुल एलएनजी निर्यात क्षमता में लगभग 17 प्रतिशत की कमी आई है। कतर एनर्जी के अधिकारियों के अनुसार, इस नुकसान की मरम्मत में 3 से 5 साल का समय लग सकता है, जिससे यह एक दीर्घकालिक संकट बन गया है। इस हमले से कतर को प्रति वर्ष लगभग 20 अरब डॉलर के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। यह हमला केवल कतर तक सीमित नहीं है, बल्कि

वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। भारत अपनी प्राकृतिक गैस जरूरतों का लगभग 40 से 50 प्रतिशत कतर से आयात करता है, इसलिए यह स्थिति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है। मध्य पूर्व से चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को तेल का लगभग 75 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस का 59 प्रतिशत निर्यात होता है। इन सभी अर्थव्यवस्थाओं को तेल-गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। होटल, रेस्टोरेंट, पर्यटन और उत्पादन जैसे कई क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने कहा है कि खाद्य सेवा उद्योग का 75 फिसदी हिस्सा एलपीजी पर निर्भर है और लंबे समय तक इसकी कमी रहने से अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन 12 से 13 हजार करोड़ रुपए नुकसान हो सकता है। युद्ध के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 39 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई हैं। ईंधन और प्राकृतिक गैस की बढ़ती कीमतों से दुनिया भर में माल ढुलाई और उत्पादन लागत बढ़ गई है, जिससे महंगाई बढ़ रही है। भारत में भी प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए और इंडस्ट्रियल डिजल 22 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गई है। दुनिया भर में यूरिया की कुल आपूर्ति में कतर का लगभग 10 प्रतिशत योगदान है। लेकिन ईरानी हमले की वजह से कतर के कई प्लांट बंद हैं, जिससे भारत में भी खाद की किल्लत बढ़ सकती है। यदि यह संघर्ष लंबा चलता है, तो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल सकता है। ऊर्जा और खाद्य कीमतों में वृद्धि ने वैश्विक मुद्रास्फीति को बढ़ाया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर के अनुमान घटाए हैं। विकासशील देशों में पूंजी प्रवाह कम हुआ है। कई देशों ने अपने रक्षा बजट बढ़ा दिए हैं, जिससे सामाजिक और विकासात्मक खर्चों पर दबाव बढ़ा है।

## ईंधन की कमी से जूझ रही दुनिया, हर देश के सामने संकट, पाबंदियों के चलते जनता बेहाल



हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। स्लोवाकिया और स्लोवेनिया जैसे यूरोपीय देशों में भी डीजल खरीद पर सीमा तय कर दी गई है। इस तरह यह संकट अब किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। देखा जाये तो यह तेल संकट केवल कीमतों का खेल नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का नया अध्याय है। ऊर्जा आपूर्ति पर नियंत्रण रखने वाले देश अब निर्णायक बल बन चुके हैं। जो देश आत्मनिर्भर नहीं हैं, वे नीतिगत गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम, राशनिंग और आवामगमन पर नियंत्रण जैसे कदम बताते हैं कि सरकारें अब युद्धकालीन नीतियों को शांतकाल में लागू कर रही हैं। इसके अलावा, यह संकट आने वाले समय में कई बड़े बदलावों का संकेत दे रहा है। एक तो, ऊर्जा सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा का केंद्र बन गई। इसके अलावा, डिजिटल निगरानी और संसाधन नियंत्रण बढ़ेगा, जिससे नागरिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। साथ ही, आपूर्ति श्रृंखला टूटने से खाद्य संकट और महंगाई चरम पर पहुंच सकती है। सबसे अहम बात यह है कि यह संकट देशों की मजबूत कर रहा है कि वह कल्पित ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से बढ़ें। लेकिन जब तक यह बदलाव पूरी तरह नहीं होता, तब तक जनता को कड़े प्रतिबंध और कटिपन फैसलों का सामना करना ही होगा। बहलहाल, तेल संकट ने दुनिया को आइना दिखा दिया है। यह साफ है कि आने वाले समय में ऊर्जा ही असली शक्ति होगी। सरकारें जितनी जल्दी इस सच्चाई को समझेंगी, उतना ही बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल, हालात यह कहते हैं कि दुनिया एक लंबे संघर्ष की ओर बढ़ रही है, जहां हर देश अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है।

## मौलिक चिंतन

दिशे इंसान को मजबूत भी करते हैं और मजबूर भी!



विनय संवगेची

## तेज होती हथियारों की होड़ और अस्थिर होती विश्व व्यवस्था



ललित गर्ग

आज हर देश अपनी सुरक्षा के नाम पर हथियार खरीद रहा है, सेना को मजबूत कर रहा है और सैन्य बजट बढ़ा रहा है। यह एक ऐसी दौड़ बन गई है जिसमें कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन विडंबना यह है कि जितने अधिक हथियार बढ़ रहे हैं, दुनिया उतनी ही असुरक्षित होती जा रही है। सुरक्षा की यह मानसिकता वास्तव में असुरक्षा का ही परिणाम है। एक देश हथियार बढ़ाता है तो दूसरा देश भी हथियार बढ़ाता है और इस तरह एक अविश्वस का वातावरण बन जाता है। यह अविश्वस ही युद्ध की जमीन तैयार करता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में दुनिया का सैन्य खर्च कई गुना बढ़ जाएगा और यह पैसा मानव विकास के बजाय विनाश की तैयारी में खर्च होगा। यह स्थिति मानव सभ्यता के लिए शुभ संकेत नहीं है। पश्चिम एशिया का संकट इस समय दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता दिखाई दे रहा है। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते हमले, समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर तनाव और बड़े देशों की प्रत्यक्ष या परोक्ष भागीदारी ने इस क्षेत्र को युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा समुद्री मार्ग खोलने की चेतावनी को खारिज करते हुए ईरान ने इजरायल पर हमलों का नया दौर शुरू किया है, जिससे यह संकट और अधिक गंभीर हो गया है। यदि यह संघर्ष लंबा चलता है तो इसका प्रभाव केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि यह क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है। दुनिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल और गैस पर निर्भर है और पश्चिम एशिया तेल उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र

है। यदि वहां युद्ध बढ़ता है या समुद्री मार्ग बाधित होते हैं तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। तेल महंगा होगा तो पेट्रोल-डीजल महंगा होगा, परिवहन महंगा होगा, उत्पादन लागत बढ़ेगी और अंततः हर वस्तु महंगी हो जाएगी। यानी एक वैश्विक महंगाई का दौर शुरू हो सकता है। महंगाई बढ़ने से गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर भी जा सकती है। पहले से ही कई देश आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और यदि ऊर्जा संकट बढ़ता है तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। भारत जैसे देश भी इस स्थिति से अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। इसी खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति, पेट्रोल-डीजल, गैस और उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रियों के साथ आपात बैठक कर ऊर्जा आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने और संभावित संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। केवल केंद्र सरकार की तैयारी पर्याप्त नहीं होगी, राज्य सरकारों को भी इस स्थिति को समझते हुए ऊर्जा संरक्षण, आपूर्ति प्रबंधन और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने होंगे। इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ी चिंता यह है कि दुनिया युद्ध को रोकने के बजाय उसकी तैयारी ज्यादा कर रही है। युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे रोकना बहुत कठिन



है। इतिहास गवाह है कि कई युद्ध ऐसे हुए जो कुछ दिनों के लिए शुरू हुए लेकिन वर्षों तक चलते रहे और उन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज भी यदि पश्चिम एशिया का युद्ध फैलता है तो यह केवल दो या तीन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बड़े देशों की भागीदारी से यह वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकता है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि विश्व के बड़े देश आगे बढ़कर युद्ध विराम की पहल करें और वार्ता का रास्ता निकालें। अमेरिका की भूमिका इस पूरे संकट में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अमेरिका चाहे तो वह इजरायल पर दबाव डाल सकता है, ईरान के साथ वार्ता शुरू करा सकता है और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से युद्ध विराम की दिशा में कदम उठा सकता है। कूटनीति का रास्ता हमेशा युद्ध से बेहतर होता है, क्योंकि युद्ध में अंततः नुकसान सभी का होता है। युद्ध में सैनिक मरते हैं, नागरिक मरते हैं, शहर बर्बाद होते हैं, अर्थव्यवस्था टूटती है और आने वाली पीढ़ियां तक उसके दुष्परिणाम झेलती हैं। इसलिए आज दुनिया को हथियारों की दौड़ नहीं, शांति की दौड़ की जरूरत है। हथियारों की होड़ का सही अर्थ है कि इससे विकास रुक जाता है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां आज भी लोग गरीबी, भूख, बीमारी और अशिक्षा से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने के बजाय हथियारों पर खर्च बढ़ा रही हैं। यह मानवता के साथ एक तरह का अन्याय है। यदि दुनिया का सैन्य बजट का एक छोटा

होता है। इतिहास गवाह है कि कई युद्ध ऐसे हुए जो कुछ दिनों के लिए शुरू हुए लेकिन वर्षों तक चलते रहे और उन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज भी यदि पश्चिम एशिया का युद्ध फैलता है तो यह केवल दो या तीन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बड़े देशों की भागीदारी से यह वैश्विक संघर्ष का रूप ले सकता है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि विश्व के बड़े देश आगे बढ़कर युद्ध विराम की पहल करें और वार्ता का रास्ता निकालें। अमेरिका की भूमिका इस पूरे संकट में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अमेरिका चाहे तो वह इजरायल पर दबाव डाल सकता है, ईरान के साथ वार्ता शुरू करा सकता है और संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से युद्ध विराम की दिशा में कदम उठा सकता है। कूटनीति का रास्ता हमेशा युद्ध से बेहतर होता है, क्योंकि युद्ध में अंततः नुकसान सभी का होता है। युद्ध में सैनिक मरते हैं, नागरिक मरते हैं, शहर बर्बाद होते हैं, अर्थव्यवस्था टूटती है और आने वाली पीढ़ियां तक उसके दुष्परिणाम झेलती हैं। इसलिए आज दुनिया को हथियारों की दौड़ नहीं, शांति की दौड़ की जरूरत है। हथियारों की होड़ का सही अर्थ है कि इससे विकास रुक जाता है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां आज भी लोग गरीबी, भूख, बीमारी और अशिक्षा से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ाने के बजाय हथियारों पर खर्च बढ़ा रही हैं। यह मानवता के साथ एक तरह का अन्याय है। यदि दुनिया का सैन्य बजट का एक छोटा

हिससा भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च कर दिया जाए तो दुनिया से गरीबी और भूख को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से दुनिया की राजनीति अभी भी शक्ति संतुलन और सैन्य प्रभुत्व के इर्द-गिर्द घूम रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व ने तुरंत यह समझें कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, विज्ञान, शिक्षा और मानव विकास में होती है। जो देश अपने नागरिकों को बेहतर जीवन देता है, वही वास्तव में शक्तिशाली देश होता है। युद्ध और हथियार केवल विनाश लाते हैं, विकास नहीं। इसलिए दुनिया को यह तय करना होगा कि उसे हथियारों की दुनिया बनानी है या मानवता की दुनिया। यदि वर्तमान परिस्थितियों में युद्ध नहीं रुके और हथियारों की होड़ इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले वर्षों में दुनिया की महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ऊर्जा संकट और सामाजिक अस्थिरता जैसे अनेक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थिति पूरी मानवता के लिए खतरनाक होगी। इसलिए अब समय आ गया है कि विश्व के सभी देश अपने संकीर्ण राष्ट्रीय हितों से ऊपर उठकर वैश्विक हितों के बारे में सोचें और युद्ध के बजाय शांति, सहयोग और सहअस्तित्व का मार्ग अपनाएं। मानव सभ्यता का भविष्य हथियारों से नहीं, बल्कि शांति, संवाद और सहयोग से सुरक्षित हो सकता है। यही समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और यही मानवता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। युद्ध का अंधेरा मानवता को केवल विनाश, महंगाई, भय और अस्थिरता देता है, जबकि दुनिया को आशा शांति, संवाद और स्थिरता का उजाला चाहिए, और इस दिशा में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। आज वैश्विक परिदृश्य में भारत केवल एक उपरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक नैतिक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का व्यक्तित्व एक ऐसे विश्व नेता के रूप में उभरा है जो युद्ध नहीं, संवाद-संघर्ष नहीं, सहयोग और हिंसा नहीं, सहअस्तित्व की बात करता है। भारत बुद्ध, महावीर और गांधी की अहिंसा की परंपरा का देश है, इसलिए भारत यदि सक्रिय कूटनीतिक पहल करे, युद्धरत देशों के बीच संवाद का सेतु बने, संयुक्तराष्ट्र के मंच पर युद्ध विराम की ठोस पहल करे, तो यह विश्व राजनीति को नई दिशा दे सकता है। मोदी यदि शांति, अहिंसा, वैश्विक संवाद और आर्थिक सहयोग के चार सूत्रों पर विश्व को साथ लाने की पहल करें तो भारत वास्तव में विश्व शांति का मार्गदर्शक बन सकता है और युद्ध की दिशा में बढ़ती दुनिया को शांति और स्थिरता की दिशा में मोड़ने में ऐतिहासिक भूमिका निभा सकता है।

## संक्षिप्त समाचार

तेज रफतार ट्रैक्टर की टक्कर से ऑटो सवार दो लोगों की मौत, दो घायल



फतेहपुर, एजेंसी। गाजीपुर थाना क्षेत्र के नरतौली में तेज रफतार ट्रैक्टर और ऑटो की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। इससे ऑटो सवार दो लोगों की मौत हो गई। जबकि दो लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों मृतकों की पहचान कराने का प्रयास कर रही है।

## कैथी टोल प्लाजा पर बाबा रामदेव का स्वागत

वाराणसी। योगगुरु बाबा रामदेव रविवार को मऊ से बनारस पहुंचे। कैथी टोल प्लाजा पर मार्कंडेय महादेव के पुजारी मुन्ना गिरि, रिकू गौरव गिरि ने वैदिक मंत्रोच्चारण से स्वागत किया। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष विजय यादव, एक आर्यवेद कॉलेज के विद्यार्थियों ने माल्यार्पण किया। बाबा रामदेव ने सभी को योग और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। वह यहां से रिंग रोड होकर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से रवाना हो गए।



## श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर लगा भंडारा

लखनऊ, एजेंसी। एशबाग के मोतीझील स्थित माधव कला मंडप में चल रहा सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का शनिवार को समापन हुआ। 51 सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। मुख्य अतिथि महापीर सुषमा खर्कवाल रही। यह आयोजन ममता चेरिटैबल ट्रस्ट एवं समिति मालवीय नगर लखनऊ सोसाइटी और से किया गया। संस्थापक एवं भाजपा अवध क्षेत्र के उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा, कथा व्यास पं. रामशरण शास्त्री, मुख्य यजमान राजीव मिश्रा, समिति के कोषाध्यक्ष गौरव पांडेय, अधिवक्ता संतोष माहेश्वरी, उपाध्यक्ष जितेश श्रीवास्तव, अमित गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे।

## जब नेताओं पर बात आई तो शुरू हुई लड़ाई, सड़कों पर पब्लिक

अलीगढ़, एजेंसी। अलीगढ़ में बिजली अफसरों की मीटिंग विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने बिजली कटौती और अनियमितता पर अफसरों को घेरा। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के कुछ सवाल का अफसरों ने जवाब दिया तो कुछ पर चुप्पी साधे बैठे रहे। मार्च का महीना बिजली संकट से भरा रहा। भीषण गर्मी हो या फिर आंधी-पानी बिजली की किल्लत से अलीगढ़ के लाखों उपभोक्ता परेशान रहे। प्री-पेड स्मार्ट मीटर के ऑटो कट ने जनता को उग्र प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। जिसमें उपभोक्ताओं ने उपकेंद्रों पर तालाबंदी और बिजली गूल कर जमकर हंगामा किया। जनता ने जनप्रतिनिधियों को घेरा तो वह जिले से लेकर शासन तक आवाज पहुंचाई। अपनी साख पर आई तो 22 मार्च को सिक्रेट हाउस में बिजली अफसरों की मीटिंग विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने बिजली कटौती और अनियमितता पर अफसरों को घेरा। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के कुछ सवाल का अफसरों ने जवाब दिया तो कुछ पर चुप्पी साधे बैठे रहे। तीन घंटे चली इस बैठक में जनता को कितना फायदा पहुंचेगा यह तो आने वाला समय की बताएगा? क्रासी बाईपास स्थित सिक्रेट हाउस सभागार में रविवार को बिजली विभाग के अधिकारियों और जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ सुझाव व मार्गदर्शन की बैठक हुई। दोपहर 12 बजे से शुरू हुई बैठक में जेई से लेकर एई, एफडीओ, एक्सईएन, एसई और मुख्य अभियंता रहे। जिसमें एक-एक जनप्रतिनिधियों ने विभागीय अधिकारियों को घेरना शुरू किया। तीन बजे तक चली बैठक में मार्गदर्शन व सुझाव कम शिकायतों का दौर ज्यादा चला। यही नहीं जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों द्वारा फोन न रिसीव करने की व्यथा भी बताई। एक जनप्रतिनिधि ने प्री-पेड स्मार्ट मीटर का अपना दर्द बयां किया। कहा कि मेरे घर की बिजली कट गई। पूछने पर पता चला बकाया है। बकाया व रिचार्ज करने के दो घंटे बाद बिजली जोड़ी। इसके लिए एक्सईएन को पांच से छह बार फोन करना पड़ा। जब हमारा यह हाल है तो आम जनता को क्या होगा? खेर में तैनात बाबू रामवीर यादव ने भाजपा कार्यकर्ता से टयूबवेल कनेक्शन के नाम पर 25 हजार रुपये ले लिए। यह मुद्दा भी जनप्रतिनिधियों ने उठाया। जिस पर मुख्य अभियंता ने कड़ी कार्रवाई की बात कही।

गर्भावस्था की सही उम्र तय करने में मदद, खतरे की भी पहचान  
भारत ने बनाया देसी मॉडल

अलीगढ़, एजेंसी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) बताएगा कि कब जन्म होगा? भारत ने देसी मॉडल बनाया है। गर्भावस्था की सही उम्र तय करने में मदद मिलेगी। समय से पहले जन्म के खतरे की भी पहचान होगी। 12 हजार से ज्यादा गर्भवती महिलाओं के डेटा पर आधारित देश का सबसे बड़ा अध्ययन किया गया है।

गर्भ में पल रहे शिशु का जन्म कब होगा, इसका अंदाजा अब सिर्फ अनुमान या विदेशी फॉर्मूला पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत ने पहली बार अपने डेटा पर आधारित ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मॉडल तैयार किया है, जो गर्भावस्था की सही उम्र का ज्यादा सटीक आकलन कर सकता है और समय से पहले जन्म (प्री-टर्म) के खतरे की पहचान भी कर सकता है।

अब तक देश में गर्भावस्था की अवधि तय करने के लिए मुख्य रूप से विदेशी मॉडल जैसे हेडलॉक और इंटग्रेथो का इस्तेमाल होता रहा है, जो पश्चिमी आबादी के डेटा पर आधारित हैं। लेकिन भारतीय महिलाओं की शारीरिक, पोषण और सामाजिक परिस्थितियां अलग होने के कारण इन मॉडलों की सटीकता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 'गर्भ-इनि' कार्यक्रम तैयार किया है, जिसे सोमवार को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट



सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से लॉन्च किया जाएगा।

इसके तहत देश में पहली बार बड़े स्तर पर गर्भवती महिलाओं का डाटा इकट्ठा कर देसी मॉडल तैयार किया गया है। इस अध्ययन में 12 हजार से अधिक महिलाओं को शामिल किया गया, जिनमें से करीब 11 हजार के परिणाम दर्ज किए गए हैं।

## डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाती कई महिलाएं

जैव प्रौद्योगिकी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, यह मॉडल खास तौर पर उन महिलाओं के लिए उपयोगी होगा, जो गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाती या जिन्हें अपनी आखिरी माहवारी

(एलएमपी) की सही जानकारी नहीं होती। ऐसे मामलों में गर्भ की सही उम्र का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे इलाज और देखभाल प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस तरह के एआई टूल्स को स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल किया जाएगा, ताकि गर्भवती महिलाओं की निगरानी और फॉलोअप बेहतर हो सके।

## हर चौथे नवजात की मौत का कारण प्री-टर्म डिलीवरी

अलीगढ़ स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (जेएनएमसी) के अध्ययन के मुताबिक, पश्चिमी यूपी सहित देश में नवजात मौतों का सबसे बड़ा कारण अब समय से पहले जन्म (प्री-टर्म बर्थ) बन चुका है। भारत में हर चार में से एक नवजात की मौत प्री-टर्म जन्म से जुड़ी जटिलताओं के कारण होती है। अलीगढ़ में जन्मे 264 शिशुओं पर किए गए अध्ययन में 29 नवजात बच्चे समय से पहले (34 सप्ताह से कम) और 71 नवजात बच्चे के बाद जन्मे पाए गए। शोधकर्ताओं का कहना है कि टीबी, निर्मोनिया या कुपोषण जैसे मुद्दों पर लगातार चर्चा होती है, लेकिन प्री-टर्म बर्थ अब भी स्वास्थ्य नीति और जनजागरूकता के केंद्र में नहीं आ पाया है।

## सीएम योगी आज करेंगे एआई-आधारित निवेश मित्र 3.0 का शुभारंभ, निवेश की प्रक्रिया को तेज करने का लक्ष्य



लखनऊ, एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को लोकभवन में एआई-आधारित उन्नत सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र 3.0 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल प्रदेश में निवेश बढ़ाने, उद्योग स्थापना प्रक्रिया को सरल बनाने और उत्तर प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। साथ ही यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम-2025 का भी शुभारंभ होगा।

कार्यक्रम में मैनुफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों की 85 कंपनियों को लैटरल ऑफ कम्फर्ट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, भूमि आवंटन पत्र और 2,781.12 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। डीबीएफओटी (पीपीपी) मॉडल पर आधारित प्लग-एंड-प्ले इंडस्ट्रियल शेड्स योजना भी शुरू होगी, जिससे निवेशक तुरंत उत्पादन शुरू कर सकेंगे। इन्वेस्ट यूपी दो कंपनियों के साथ एंटरप्रेनोरशिप डेवलपमेंट सेल और द कन्वर्जेंस फाउंडेशन के साथ स्किल कनेक्ट सेल हेतु एमओयू करेगा। कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे।

## सीएम ग्रीड की सड़कों पर मानकों की अनदेखी

अलीगढ़, एजेंसी। शहर में इन दिनों सीएम ग्रीड योजना से 11 सड़कों का निर्माण 250 करोड़ लागत से हो रहा है। एक तरफ एक साथ 11 सड़कों के निर्माण से शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। दूसरी ओर इनके निर्माण में मानकों की अनदेखी पर आमजन लगातार शोर मचा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के स्तर से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि, नगर निगम ने निर्माण एजेंसी पर कुछ सड़कों के निर्माण में जुर्माना लगाकर फिर से निर्माण कराने के निर्देश दिए हैं।

शहर में सड़क निर्माण में सबसे ज्यादा सवाल रामघाट रोड के निर्माण में खड़े हो रहे हैं। जहां निर्माण की धूमि गति के साथ-साथ सड़क निर्माण में क्रासी थो से किशनपुर तक सीवर लाइन व उसके टैंक ही दबा दिए गए। तब किसी का ध्यान नहीं गया। इन सड़कों के निर्माण में ये शर्त पहले से थी कि पहले सभी तरह की पाइपलाइन व वायरिंग लाइन अंडरग्राउंड होंगी। उसके बाद सड़क की लेयर बिछेगी। अब जब सीवर लाइन की याद आई तो किशनपुर के आगे अंडरग्राउंड टैंकों को छोड़ा जा रहा है। अब पूरे में सीवर लाइन कैसे बिछेगी। इस पर किसी ने तस्वीर साफ नहीं की है। इसी तरह दोनपुर में एक सड़क की सड़क पूरी बन गई। तब उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा हुआ। अब उसे नए सिरे से बनाने का निर्देश दिया है। कमीशन यही हाल अन्य सड़कों का है। आईटीआई रोड इन सड़कों का हो रहा निर्माण

## राज्य स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत महानगर के 20 पार्कों में लगेंगे ओपन जिम, नगर निगम ने शुरू की प्रक्रिया

गोरखपुर, एजेंसी। राज्य स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत महानगर के 20 पार्कों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के लिए राज्य स्तरीय व्यय वित्त समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पहले ही प्रदान कर दी गई थी। अब इसके लिए नगर निगम की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है, जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा।

इस परियोजना पर लगभग दो करोड़ चार लाख 60 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत शहर के चयनित 20 पार्कों में आधुनिक ओपन जिम लगाए जाएंगे, जिनमें स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए करीब 15 प्रकार के अत्याधुनिक जिम उपकरण उपलब्ध होंगे। इन उपकरणों का उपयोग आम नागरिक निशुल्क कर सकेंगे।

नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के निर्देश पर नगर निगम ने इस परियोजना का प्रस्ताव तैयार कर मिशन निदेशालय को भेजा था, जिसे स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया की गई है। बता दें कि नगर निगम की भूमि पर स्थित पार्कों में जिम स्थापित



किए जाएंगे। प्रत्येक ओपन जिम लगभग 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा, जिससे लोगों को खुले वातावरण में व्यायाम करने की सुविधा मिल सके। अधिकारियों का कहना है कि इस पार्कों में ओपन जिम बनने से शहर के नागरिकों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और पार्कों में लोगों की

भागीदारी भी बढ़ेगी। नगर निगम के मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने बताया कि ओपन जिम की स्थापना के बाद इनके संचालन, रखरखाव और अनुरक्षण की जिम्मेदारी नगर निगम गोरखपुर की ओर से अपने संसाधनों से निभाई जाएगी। टेंडर इसके लिए कर दिया गया है, जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा।

## ताजमहल की सुरक्षा में चूक: स्मारक के पूर्वी गेट तक पहुंचा हरियाणा का स्कूटर

आगरा, एजेंसी। ताजमहल पर पुलिस के चेकिंग बैरियर से आगे पेट्रोल वाहन प्रतिबंधित है। सिर्फ पास धारक और स्थानीय निवासी ही अपना आधार कार्ड दिखाकर वाहन लेकर जा सकते हैं। बैरियर पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और चेकिंग होती है। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। एक व्यक्ति हरियाणा के नंबर की एक स्कूटर बैरियर पर करते हुए पूर्वी गेट तक लेकर गया और वापस भी लौटा। सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे किसी पुलिसकर्मी की नजर स्कूटर पर नहीं पड़ी। रविवार को इसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके बाद एसीपी ताज सुरक्षा में मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।

वायरल फोटो शनिवार दोपहर की बताई जा रही है। ताजमहल पर ईद की नमाज के दौरान प्रवेश



निशुल्क था। इसके बाद भी ताजमहल पर पर्यटकों की भारी भीड़ थी। ताजमहल पर पुलिस के चेकिंग बैरियर से आगे पेट्रोल वाहन प्रतिबंधित है।

सिर्फ पास धारक और स्थानीय निवासी ही अपना आधार कार्ड दिखाकर वाहन लेकर जा सकते हैं। बैरियर पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और चेकिंग होती है। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी

हरियाणा नंबर की लाल रंग की स्कूटर लेकर एक व्यक्ति बैरियर पर कर पूर्वी गेट के पास पहुंच गया। वहीं स्कूटर खड़ी कर काफी देर रुका और वापस लौट गया। किसी जिम्मेदार ने उसे रोका नहीं। फोटो वायरल होने के बाद सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक की चर्चा होने लगी। एसीपी ताज सुरक्षा पिथूब कांत राय ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। जांच की जा रही है।

## रोहनिया विधायक ने अपना दल एस के नामित पार्षद का किया सम्मान



वाराणसी, एजेंसी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नामित अपना दल (एस) के पार्षद कमलेश गुप्ता के आवास पर स्वागत समारोह हुआ। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय नागरिकों ने उनका अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि रोहनिया विधायक डॉ. सुनील पटेल और आराजी लाइन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉ. महेंद्र सिंह रहते रहे। उन्होंने नामित पार्षद कमलेश

गुप्ता को पार्टी का पट्टा पहनाकर, पुष्पगुच्छ, मोमेटो भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही भाजपा के नामित पार्षद दिनेश शर्मा और अजय जायसवाल उर्फ पप्पू का भी सम्मान हुआ। अपना दल (एस) के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र पटेल, श्याम बाली पटेल, जिला अध्यक्ष राजेंद्र पटेल, प्रदेश महासचिव उमेश पटेल, प्रदेश सचिव सियाराम पटेल शामिल रहे।

## जो स्मार्टफोन नहीं चला सकते, उन्हें बाहर करो

## जैश-ए-मोहम्मद ने दिया था जिहादी को फरमान, मिला था ये संदेश

गाजियाबाद, एजेंसी। जासूसी मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने मुख्य आरोपी शावेज उर्फ जिहादी को फरमान दिया था कि जो स्मार्टफोन नहीं चला सकते, उन्हें बाहर करो। कोड वर्ड में बातचीत का दबाव रहता था। ताकि पकड़े जाने पर राज न खुले। ऑनलाइन ट्रेनिंग और वीडियो के जरिये कोडिंग की जानकारी दी जाती थी।

पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और फरातुल्ला गौरी रूप से जुड़े छह संदिग्धों की गिरफ्तारी के मामले में जांच जैसे-जैसे बढ़ रही है, सनसनीखेज खुलासा हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, प्रकरण की जांच कर रही टीम को मुख्य आरोपी शावेज उर्फ जिहादी के मोबाइल फोन से एक अहम संदेश मिला है।

इसमें उसने पाकिस्तान में बैठे जैश के हैंडलर को सात लोगों की सूची भेजी थी। सूची में नाम के साथ उनकी शिक्षा, पेशा और स्मार्टफोन चलाने की क्षमता का भी उल्लेख था। सूची में एक व्यक्ति पश्चिम बंगाल और एक बांग्लादेश का था। जवाब में जैश से निर्देश मिला था कि कम पढ़े-लिखे लोग भी शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन जो

## जासूसी मामले में सनसनीखेज खुलासा

कोड वर्ड में बातचीत का रहता था दबाव, ताकि पकड़े जाने पर राज न खुले

ऑनलाइन ट्रेनिंग और वीडियो के जरिये दी जाती थी कोडिंग की जानकारी

स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते, उन्हें बाहर कर दिया जाए। साथ ही सूची को घटकर तीन लोगों तक सीमित करने के लिए कहा गया था। इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियों का नजरिया भी बदला है। पेशे से वकील इकराम अली को नेटवर्क में शामिल करने के पीछे जिहादी की मंशा कानूनी पेचीदगियों से निपटने की थी। वहीं जुनैद को एलाएलबी में दाखिला दिलाकर पढ़े-लिखे और कानूनी समझ रखने वाले लोगों का नेटवर्क तैयार किया जाना था।

जांच एजेंसियों को पूछताछ में जिहादी ने यह भी बताया है कि गिरोह अधिकतर बातचीत कोड वर्ड में करता था। कई बार कोड को समझने में दिक्कत होती थी, ऐसे में वह इकराम की मदद लेता था। संदेशों के आदान-प्रदान में भी कोड वर्ड

का इस्तेमाल अनिवार्य था। इसके लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती थी। संदिग्धों को कई वीडियो भेजकर भी कोडिंग समझाने का प्रयास किया गया था। पुलिस को उनके मोबाइल फोन से ऐसे कई वीडियो मिले हैं, जिन्हें जांच में शामिल किया गया है। इस बारे में डीसीपी प्रामोण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि एनआईए और इंटेलिजेंस की टीम मामले को गहन जांच कर रही है। इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। संगठन विस्तार के लिए तैयारी से कर रहा था काम जांच में यह भी सामने आया है कि जिहादी संगठन विस्तार के लिए तैयारी से काम कर रहा था। उसकी गतिविधियां गाजियाबाद तक ही सीमित नहीं थीं। वह और नाहल गांव के उसके साथी जुनैद, फरदीन, इकराम, फजरु और जावेद अक्सर जूम मीटिंग के जरिये जुड़ते थे और दिनभर की गतिविधियों की समीक्षा करते थे।

जिहादी को जुनैद और फरदीन की ओर से भी कुछ लोगों की सूची मिली थी। इन्हें देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की तैयारी थी। पुलिस ने सभी आरोपियों के बैंक खातों की भी जांच शुरू कर दी है।

# शेयर बाजार तेजी के साथ बंद सेंसेक्स 1,372, निफ्टी 399 अंक उछला।

मुंबई।

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को बंद के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन ये तेजी मध्यपर्व में संघर्ष सामाप्त होने की संभावनाओं के कारण आई है। इससे घरेलू बाजार में भी खरीददारी हलकी रही।

ऑटो और बैंक शेयरों में भी उछाल आया, जिससे दोनों प्रमुख बैंचमार्क अपने दिन के उच्चतम स्तर के करीब बंद हुए। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई 30 1,372.06 अंकों की बढ़त के साथ 74,068.45 पर बंद हुआ जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 399.75 अंक उछलकर 22,912.40 पर था। आज सेसेक्स एक समय 74,489.39 पर दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया जबकि निफ्टी एक समय 23,057.30 तक पहुंच गया। व्यापक बाजारों ने 'बैचमार्क'

सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी मिडकैप में 2.60 फीसदी की तेजी रही जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 2.63 फीसदी की बढ़त रही।

ऑटो सेक्टर में 2.43 प्रतिशत की बढ़त दर्ज रही जबकि निफ्टी मीडिया में 3.45 प्रतिशत की तेजी आई। निफ्टी बैंक सेक्टर 2.27 फीसदी की तेजी रही।

निफ्टी आईटी में 1.72 फीसदी जबकि निफ्टी एफएमसीजी में 1.25 फीसदी की तेजी आई। आज इंडिगो और एलएंडटी के शेयरों में सबसे ज्यादा 5.49 फीसदी और 5.17 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। इसके बाद बजाज फाइनेंस, इटरनल, एशियन पेंट्स और अपोलो हॉस्पिटल के शेयरों में भी अच्छी तेजी रही। कोल इंडिया, पावरग्रिड, सन फार्मा और सिप्ला के शेयरों में गिरावट आई। बाजार में आई तेजी से बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण में 7.74 लाख करोड़ रुपए की

बढ़त आई। इससे गत दिवस के 15.11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 422.85 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार एक ही दिन में निवेशकों को करीब 8 लाख करोड़ रुपए का लाभ हुआ। इससे पहले आज सुबह बाजार ने मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की। एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुख और अमेरिका तथा ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों ने निवेशकों के मनोबल को बढ़ाया।

सेंसेक्स 500 से अधिक अंकों की बढ़त के साथ 74,212.47 पर खुला।

सुबह शुरुआत के बाद सेसेक्स 1067.47 अंकों की बढ़त के साथ लगभग 73,763.86 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी-50 भी मजबूत शुरुआत के साथ 22,878 पर खुला।

बाजार में इस तेजी के पीछे प्रमुख कारण अमेरिका और ईरान



के बीच संभावित बातचीत की खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सोमवार को कहा था कि दोनों देशों के बीच

सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई है, जिससे लंबे समय से चले आ रहे तनाव का समाधान निकल सकता है।

स्तर पर तनाव कम होने की उम्मीद से निवेशकों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिसका असर बाजार में तेजी के रूप में दिखता है।

## राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी

जयपुर।

राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को पेट्रोल 104.72 रुपये और डीजल 90.21 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर हैं। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल का दायरा 104.72 से 105.21 रुपये और डीजल का 90.21 से 90.65 रुपये के बीच रहा। राजधानी में स्थिरता के बावजूद राज्य के अन्य जिलों में कीमतों में हल्की बढ़त और गिरावट देखी गई। अजमेर में पेट्रोल 0.17 रुपये बढ़कर 104.53 रुपये और अलवर में 0.36 रुपये घटकर 104.83 रुपये प्रति लीटर रही। बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में दाम लगभग स्थिर 106.20 से 106.21 रुपये के बीच हैं। नागौर में सबसे अधिक बढ़ती दर्ज की गई, पेट्रोल 1.01 रुपये बढ़कर 106.29 रुपये प्रति लीटर हुआ। दौसा और कोटा में क्रमशः 0.70 और 0.67 रुपये की बढ़त दर्ज की गई। वहीं, डीजल में 0.69 रुपये और जोधपुर में 0.34 रुपये की गिरावट हुई। झुंझुनू, चूरू और सिरोंही में भी कीमतें कम हुईं। डीजल की कीमत जयपुर में स्थिर बनी रही, लेकिन अन्य जिलों में



बदलाव नजर आया। अजमेर में 0.16 रुपये की बढ़त हुई और अलवर में 0.32 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। नागौर में 0.93 रुपये की सबसे बड़ी बढ़ती हुई। दौसा और कोटा में क्रमशः 0.63 और 0.61 रुपये बढ़े, जबकि डीजल और जोधपुर में दाम घटकर क्रमशः 89.75 और 90.00 रुपये पर आ गए। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, डॉलर-रुपये का विनिमय दर और टैक्स स्ट्रक्चर ईंधन की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। उपभोक्ताओं को रोजाना रेट्स चेक करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मामूली बदलाव हमेशा संभव हैं।

## जीएसपी क्रॉप साइंस का शेयर चार प्रतिशत की बढ़त के साथ सूचीबद्ध



नई दिल्ली।

कृषि रसायन कंपनी जीएसपी क्रॉप साइंस लिमिटेड का शेयर मंगलवार को अपने निर्गम मूल्य 320 रुपए के मुकाबले 3.84 रुपए की बढ़त के साथ बीएसई पर 332.30 रुपए पर सूचीबद्ध हुआ। लिस्टिंग के बाद शेयर में और तेजी आई और यह 362.30 रुपए तक पहुंच गया, जो लगभग 13.21 फीसदी की बढ़त दर्शाता है। कंपनी का 400 करोड़ रुपये का आईपीओ 304-320 रुपये प्रति शेयर के मूल्य दायरे में आया था। अंतिम बोली के दिन आईपीओ को 1.61 गुना

अभिधान मिला, जिससे इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कंपनी ने आईपीओ से जुटाई गई 170 करोड़ रुपए की राशि का एक हिस्सा ऋण भुगतान के लिए और बाकी सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए रखने की योजना बनाई है। जीएसपी क्रॉप साइंस 39 वर्षों से अधिक समय से भारत में कीटनाशक, खरपतवारनाशक, फफूंदनाशक और पादप वृद्धि नियामकों के विकास एवं विनिर्माण में सक्रिय है।

यह एक अनुसंधान-केन्द्रित कृषि रसायन कंपनी के रूप में जानी जाती है।

## भारत का ऑयल और गैस सेक्टर पश्चिम एशिया तनाव से प्रभावित

देश में गैस सप्लाई में लगभग 45-47 एमएमएससीएमडी की गिरावट

नई दिल्ली।

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारत का ऑयल और गैस सेक्टर भारी दबाव में है।

एटीक स्टॉक ब्रोकरेज की रिपोर्ट के अनुसार इस संकट के कारण देश में गैस सप्लाई में लगभग 45-47 एमएमएससीएमडी की कमी हुई है। सबसे अधिक असर गैल पर पड़ा है, जबकि ओएनजीसी को इसका लाभ मिलने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओएनजीसी के नए प्रोजेक्ट्स जैसे दमन और केजी बेसिन में उत्पादन बढ़ने वाला है। इसके साथ ही कच्चे तेल

की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं और विंडफॉल टैक्स की वापसी की संभावना नहीं है, जिससे कंपनी की कमाई बढ़ने की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने मौजूदा स्तर पर ओएनजीसी के शेयर को आकर्षक बताया और 'बाय' की सलाह दी। गैल को गैस सप्लाई में कमी के कारण हर महीने 250-300 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। हालांकि, सरकार की गैस पूर्ण व्यवस्था से कंपनी को कुछ

राहत मिल रही है, जिससे महंगी गैस खरीदने पर होने वाले नुकसान से बचाव हो रहा है। हाल ही में शेयर में गिरावट आई है, जिससे निवेश का मौका बन सकता है। ब्रोकरेज ने इस शेयर पर भी 'बाय' की सलाह दी है। पेट्रोनेट एलएनजी के दाहेज टर्मिनल की उपयोग क्षमता घटकर करीब 50 प्रतिशत हो गई है। इसके बावजूद कंपनी की कमाई पर ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि उसका बिजनेस



मॉडल सुरक्षित है। ब्रोकरेज ने कहा कि अब इसमें जोखिम कम है और सुधार की संभावना है। आईजीएल की बिजली फिलहाल ठीक चल रही है, लेकिन आने वाले समय में

मार्जिन पर दबाव बढ़ सकता है। सस्ती गैस की सप्लाई धीरे-धीरे कम हो रही है, जिससे अगले 2-3 साल में मार्जिन प्रभावित हो सकता है।

## टाटा पावर ने जीव्यवीएनएल के साथ अनुपूरक बिजली खरीद समझौते किए

— संयंत्र संचालन अस्थायी रूप से किया गया निलंबित

नई दिल्ली।

टाटा पावर की इकाई कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड (सीजीपीएल) ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीव्यवीएनएल) के साथ मूंदड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) के लिए अनुपूरक बिजली खरीद समझौता (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं।

कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि यह कदम मूंदड़ा स्थित संयंत्र की इकाइयों के अस्थायी निलंबन के कारण हुआ नुकसान कम करने के लिए उठाया गया है। 2 जुलाई 2025 को संयंत्र की सभी पांच इकाइयों (प्रत्येक 800 मेगावाट) का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। बंद रहने के

कारण कंपनी को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। कंपनी ने पहले ही शेयर बाजार को सूचित किया था कि गुजरात मंत्रिमंडल ने इस अनुपूरक पीपीए को मंजूरी दे दी है और इसके लिए सरकारी आदेश भी जारी किया जा चुका है। नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद ही समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते से सीजीपीएल को संयंत्र बंद रहने के दौरान भी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। टाटा पावर की योजना इसी तरह के अनुपूरक समझौते अन्य राज्यों, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के साथ करने की भी है। मूंदड़ा यूएमपीपी कच्छ, गुजरात में स्थित एक 4,000 मेगावाट का



कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। इसमें पांच इकाइयां हैं, प्रत्येक की क्षमता 800 मेगावाट। यह संयंत्र गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को बिजली आपूर्ति करता है।

कंपनी का कहना है कि अनुपूरक पीपीए से संयंत्र के अस्थायी बंद होने से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी और यह बिजली आपूर्ति की स्थिरता सुनिश्चित करेगा।

## मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सोना-चांदी के भाव में गिरावट

नई दिल्ली।

मिडिल ईस्ट में बढ़ते कूटनीतिक तनाव और ईरान-अमेरिका के बीच जुबानी टकराव ने सोना और चांदी के निवेशकों को हैरान कर दिया है। मंगलवार सुबह मस्कीटो कर्मोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। वैश्विक स्तर पर हॉर्मूज जलडमरूमध्य के बंद होने की आशंकाओं और ईरान के अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज करने की खबरों ने बाजार को हिलाकर रख दिया। अप्रैल वायदा सोना 1,36,945 रुपये प्रति 10 ग्राम

पर आ गया, जो पिछले बंद भाव से 2,315 रुपये कम है। वहीं चांदी का मई अनुबंध 2,15,765 रुपये प्रति किलोग्राम पर फिसल गया, यानी 9,569 रुपये की गिरावट। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 14,050, 22 कैरेट 12,880 और 18 कैरेट 10,541 रुपए प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है। सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमतें लगभग 4,300 डॉलर प्रति औंस पर संघर्ष कर रही हैं। इसका मुख्य कारण ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती अनिश्चितता और तेल की बढ़ती कीमतें हैं। सोमवार को जब ट्रंप ने बातचीत का संकेत दिया था, तब कीमतें थोड़ी उछली



थीं, लेकिन अब अनिश्चितता और भू-राजनीतिक दबाव ने फिर से कीमतों को नीचे धकेल दिया है। मार्च में सोना अपने शिखर से लगभग 25 प्रतिशत नीचे आ चुका है। ऊर्जा की बढ़ती कीमतें

और संभावित ब्याज दरों में वृद्धि निवेशकों के लिए सतर्क रहने का संकेत देती हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि इस समय बाजार में छोटे उतार-चढ़ाव पर जल्दबाजी में निवेश निर्णय न लें।

## बासमती चावल निर्यातक कंपनी एक्सपोर्ट्स का आईपीओ खुला

नई दिल्ली।

हरियाणा स्थित बासमती चावल निर्यातक कंपनी अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का आईपीओ मंगलवार को खुल गया। यह पेशकश पूरी तरह से नए इंडिटी शेयरों की होगी और इसमें कोई ऑफर फॉर सेल ;ओएफएसड शामिल नहीं है। कंपनी ने अपने शेयरों का प्राइस बैंड 201 से 212 रुपए प्रति शेयर तय किया है। अपर प्राइस

बैंड पर कुल इश्यू साइज 400 करोड़ रुपए का है। नॉन-लिस्टेड शेयर मंगलवार को ग्रे मार्केट में 219 रुपए पर कारोबार कर रहे थे जो आईपीओ के अपर प्राइस बैंड 212 रुपए के मुकाबले 3 फीसदी प्रीमियम दर्शाता है। इसका संकेत है कि निवेशकों में आईपीओ को लेकर सकारात्मक भावना है। ब्रोकरेज हाउस एंजल वन ने इस आईपीओ को सक्साइड फॉर लॉन्ग टर्म रेटिंग दी है। ब्रोकरेज के अनुसार अपर

प्राइस बैंड पर कंपनी का इश्यू के बाद प्राइस अनिग रेश्यो 22.26 गुना है। यह वैल्यूएशन बासमती चावल सेक्टर की अन्य लिस्टेड कंपनियों की तुलना में संतुलित माना जा रहा है। मजबूत निर्यात कारोबार और बांडेड एवं घरेलू खंड में विस्तार के अवसर इसे आकर्षक बनाते हैं। रिटेल निवेशक अधिकतम 70 शेयर प्रति आवेदन खरीद सकते हैं। जिससे 1 लॉट की कीमत 14ए840 रुपए होगी। कुल आईपीओ का 50 फीसदी



योग्य संस्थागत निवेशकों के लिए 35 फीसदी रिटेल निवेशकों के लिए और 15 फीसदी नॉन-इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के लिए रिजर्व है।

भारतीय रेलवे ने किए बड़े बदलाव, टिकट रिफंड और अपग्रेड नियम हुए सरल

8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर यात्रियों को कोई रिफंड नहीं मिलेगा

नई दिल्ली।

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और टिकट नीतियों में सुधार के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब टिकट कैन्सलेशन पर सख्ती बढ़ा दी गई है। ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच लागू होंगे। रेलवे ने कहा है कि यात्रियों को इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनानी चाहिए। नए नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री यात्रा से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करता है तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। वहीं 24 से 8 घंटे पहले रद्द करने पर केवल 50 फीसदी रिफंड मिलेगा। तीन दिन (72 घंटे) पहले रद्द करने पर भी पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि 25 फीसदी कटौती के साथ सिर्फ 75 फीसदी राशि लौटाई जाएगी। यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि अब ऑफलाइन टिकट रद्द कराने के लिए उसी स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं है जहां टिकट खरीदी गई थी। देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाकर रिफंड लिया जा सकेगा। इससे यात्रियों की भागदौड़ कम होगी और सुविधा बढ़ेगी। रेलवे ने यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। अब यात्री ट्रेन खुलने के आधे घंटे पहले तक कोच या क्लास बदल सकते हैं, यानी स्लीपर से एसी में अपग्रेड संभव होगा। इसके अलावा, अगर कोई यात्री तय स्टेशन के बजाय आगे के किसी स्टेशन से ट्रेन पकड़ना चाहता है, तो मोबाइल ऐप के जरिए बोर्डिंग पॉइंट बदलना अब आसान होगा। इन बदलावों का मकसद यात्रियों को अधिक लचीलापन देना और सीट आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।



## एचडीएफसी बैंक में चेयरमैन के इस्तीफे के बाद बाहरी जांच शुरू

नई दिल्ली।

देश के दूसरे सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी में अचानक बदलाव ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर बहस छेड़ दी है। बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने 18 मार्च 2026 से अपना पद छोड़ दिया। उन्होंने इस्तीफे में बैंक के भीतर कुछ प्रथाओं और गतिविधियों का हवाला दिया, जो उनके व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं थीं। चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया कि उनके इस्तीफे के पीछे कोई अन्य महत्वपूर्ण वजह नहीं है। बैंक ने उनके इस्तीफे में उठाए गए मुद्दों की जांच के लिए बाहरी लॉ फर्मस नियुक्त की हैं। बैंक प्रवक्ता के अनुसार यह कदम पूरी तरह प्रोएक्टिव है और इसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और तथ्यपरक समीक्षा करना है। बैंक दशकों से अपनाए गए उच्चतम गवर्नेंस मानकों के अनुरूप खुद को परखता रहा है और यह पहल उसी दिशा में उठाया गया कदम है।

## हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण, कर्ज और ब्याज बोझ बढ़ा

वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 41,173 करोड़ रुपये कर्ज लिया

शिमला।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 41,173 करोड़ रुपये कर्ज लिया और 32,004 करोड़ रुपये चुकाए। इस तरह कुल ऋण देनदारी 2025-26 में 1,03,994 करोड़ रुपये रही, जो 2026-27 में बढ़कर 1,12,319 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पिछले तीन वर्षों में कर्ज लगातार बढ़ता रहा- 2022-23 में 76,681 करोड़, 2023-24 में 85,295 करोड़ और 2024-25 में 93,625 करोड़। ब्याज भुगतान 2024-25 में 6,261 करोड़ था, जो 2025-26 में 6,693 करोड़ और 2026-27 में 7,271 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है। वेतन, पेंशन, कर्ज और ब्याज जैसी प्रतिबद्धताओं पर कुल बजट का लगभग 80 फीसदी खर्च होता है। सॉल्डिटी घटाकर 2026-27 में 859 करोड़ रुपये, 2027-28 में 911 करोड़ और 2028-29 में 965 करोड़ रुपये करने का अनुमान है। इससे पूंजीगत कार्यों और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए केवल 20 फीसदी बजट बचता है।

## एसीएमई सोलर ने राजस्थान में 155 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली शुरू की

नई दिल्ली।

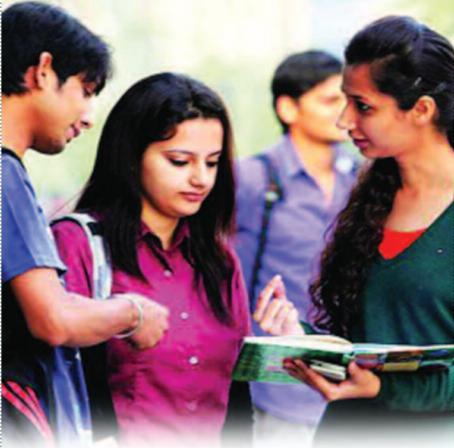
एसीएमई सोलर होल्डिंग्स ने अपनी अनुष्णी कंपनियों के माध्यम से राजस्थान में 155 मेगावाट /470.25 मेगावाट-घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) लॉन्च की है। अब कंपनी की कुल चालू बीईएसएस क्षमता 297.67 मेगावाट/951.74 मेगावाट-घंटा हो गई है। ये बैटरियां मौजूदा अंतर-राज्यीय प्रसारण प्रणाली से जुड़ी हैं और मुक्त बाजार के आधार पर संचालित होंगी। कम मांग के समय चार्ज और उच्च मांग में ऊर्जा निर्वहन से अतिरिक्त राजस्व होगा। विशेष इकाई के तहत कुल बीईएसएस क्षमता 835 मेगावाट/3,114.64 मेगावाट-घंटा है। एसीएमई सोलर का कुल नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो 8,071 मेगावाट है, जिसमें सौर, पवन, भंडारण और मिश्रित समाधान शामिल हैं। यह कदम न केवल ऊर्जा संतुलन बढ़ाएगा बल्कि ग्रिड की स्थिरता में भी योगदान देगा।

## केपीआईएल को टीएंडी कारोबार में 4,439 करोड़ के ठेके मिले

नई दिल्ली।

कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (केपीआईएल) और उसकी अनुष्णी कंपनियों को पारेषण एवं वितरण (टीएंडडी) क्षेत्र में करीब 4,439 करोड़ रुपये के ठेके मिले हैं। इनमें अफ्रीका में 400 किलोवाट पारेषण लाइन और सबस्टेशन, भारत में पारेषण लाइन परियोजनाएं और स्वीडन में एक सबस्टेशन परियोजना शामिल हैं। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि टीएंडडी कारोबार कंपनी को अपनी मजबूत बाजार स्थिति और एकीकृत क्षमताओं का लाभ उठाकर विश्वस्तरीय ईपीसी समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। उन्होंने यह भी बताया कि नए ठेकों के साथ कंपनी ने 26,000 करोड़ रुपये के वार्षिक ऑर्डर लक्ष्य को पार कर लिया है। केपीआईएल मुख्यालय: बिजली पारेषण और वितरण, भवन एवं कारखाने, जल आपूर्ति और सिंचाई, रेलवे, तेल एवं गैस पाइपलाइन, शहरी परिवहन, राजमार्ग और हवाई अड्डों में कार्य करती है। यह कंपनी ईपीसी क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञ के रूप में जानी जाती है और अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के जरिए उद्योग में मजबूत स्थिति बनाए रखती है।





## लॉग टर्म कोर्स की बजाय रोजगार पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आज के युवा

**नौकरी तलाश करने वालों के लिए ये जो अनिष्ट ठहराया आया है, संभवतः उनके लिए एक नया रास्ता खोल दिया है, जब वे कुछ नया सीख सकते हैं और अपनी प्रेक्षेत्र विशेषज्ञता को बढ़ा सकते हैं।**

एक ऑनलाइन शैक्षिक कंपनी, टलेटैज और मार्केट रिसर्च एजेंसी के एक ताजा सर्वे के अनुसार भविष्य में लंबी अवधि के करियर की योजना बनाना संभव नहीं होगा, क्योंकि विकास की गति जॉब मार्केट में बढ़ रही है और युवाओं को लगातार समय की मांग के मुताबिक खुद को ऐसे परिवेश में ढालना बेहद जरूरी होगा। वहीं इससे पहले किये गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक आधा से ज्यादा नौकरी तलाश करने वालों ने लंबी अवधि के करियर के उचित अवसर और विकास के लिए लॉकडाउन अवधि का उपयोग किया। नौकरी तलाश करने वालों के लिए ये जो अनिष्ट

ठहराया आया है, संभवतः उनके लिए एक नया रास्ता खोल दिया है, जब वे कुछ नया सीख सकते हैं और अपनी प्रेक्षेत्र विशेषज्ञता को बढ़ा सकते हैं। डेटा साइंस और पब्लिक रिलेशंस कोर्स (22 प्रतिशत), इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग (20 प्रतिशत), और वित्त और जोखिम प्रबंधन (16 प्रतिशत) शीर्ष पाठ्यक्रमों में से थे जो नौकरी ढूढ़ने वालों द्वारा चुने गए थे।

### गेजिंग इन टू द फ्यूचर

यंग इंडिया, देयर एस्पिरेशंस एंड करियर चॉइस के एक सर्वेक्षण के अनुसार, अल्पकालिक पेशेवर योजना ही एक सही रास्ता है। उत्तरदाताओं ने कहा कि वे तेजी से एक 'नौकरी' के बारे में सोचेंगे और 'करियर' नहीं, क्योंकि उनके आसपास की चीजें तेजी से बदल रही हैं और वे अगले पांच वर्षों में भी ऐसे जीवन करियर की कल्पना नहीं कर सकते हैं जब बहुत सारे वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के होते हुए भी शायद ही कुछ ऐसे होंगे जो एक उचित परिपेक्ष्य में, अनुकूल और लाभप्रद रोजगार दे सकेंगे। टलेटैज ने 20,000 छात्रों में से ऐसे उत्तरदाताओं की पहचान की है जिन्होंने इस संस्थान में पिछले वर्ष नामांकन किया था, उनमें से 60 उत्तरदाताओं ने इस सर्वे में भाग लेने के लिए फाइनल कदम रखा है। सर्वेक्षण पर आधारित यह अध्ययन लगभग पांच वर्षों तक किया गया, जिसमें से मानव संसाधन प्रमुखों, सीएक्सओ, करियर काउंसलर और समाजशास्त्रियों के उकृष्ट विचारों को संज्ञान में लिया गया, ताकि इस उभरते हुए स्फुटकाव की विस्तृत तस्वीर सामने आ सके और उम्मीदवारों को सही मार्गदर्शन मिल सके। टलेटैज के आदित्य मालिक ने एक बिजनेस समाचार पत्र में दिए गए एक वक्तव्य में बताया कि 29 साल की औसत आयु के साथ भारत 2026 तक दुनिया का सबसे युवा देश होगा। उन्होंने बताया कि वो युवा भारतीयों के विचारों को, उनके करियर के विकल्पों की संभावनाओं को और उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में समझना चाहते थे। अध्ययन में पाया गया कि डिग्रियों का कमित्त अधिग्रहण करियर का एक नया मापदंड होगा, जैसा कि उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें क्रियाशील व व्यावहारिक तजुबों से सीखना होगा और जरूरत पड़ने पर और अधिक डिग्री हासिल करनी होगी। विशेषज्ञों ने इस सर्वेक्षण पर विचार विमर्श किया और पाया कि शिक्षा सिर्फ एक बार का मामला नहीं होगा बल्कि एक सतत प्रक्रिया होगी जिसमें युवा जैसे जैसे आगे बढ़ते जायेंगे, डिग्रियां हासिल करते रहेंगे। आदित्य मालिक ने आगे बताया कि कॉर्पोरेट दुनिया के साथ बढ़ती निराशा युवाओं के जूनून को काम में परिवर्तित करने में उन्हें आगे ले जाएगी। लीक से हटकर बढ़ते हुए पाठ्यक्रमों ने नए करियर को पंख दे दिए हैं। और आज के युवा भी शायद इसे ही ज्यादा महत्त्व दे रहे हैं और अपना रुझान भी इसी पर केंद्रित कर रहे हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार के लिए आज एक बहुत बड़ा स्कोप खुल गया है, यह स्वीकार करते हुए कि वे इस बात को लेकर निश्चित नहीं थे कि यह कितना आकर्षक होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक प्रयास और परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो अगर आप एक युवा हैं और अपने करियर को लेकर गंभीर हैं तो शायद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि शार्टटर्म का कोई मनवाहा कोर्स आपको सही दिशा में ले जायेगा या फिर कोई लॉन्गटर्म वाला कोर्स।



एक जीवाश्म विज्ञानी जीवाश्मों अर्थात प्राचीन जीवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं ताकि पृथ्वी या प्रागैतिहासिक जीवन पर पिछले जीवन की पड़ताल की जा सके। यह छोटे बैक्टिरिया से लेकर विशालकाय डायनासोर तक हैं, ये जीवाश्म एक अरब वर्ष पुराने भी हो सकते हैं।

पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लाखों-करोड़ों साल पहले ही हो गई है। ऐसे कई जीव व जानवर हैं, जो सालों पूर्व धरती पर मौजूद थे, लेकिन अब वह ज्यादा नौकरी तलाश करने वालों ने लंबी अवधि के करियर के उचित अवसर और विकास के लिए लॉकडाउन अवधि का उपयोग किया। नौकरी तलाश करने वालों के लिए ये जो अनिष्ट

### वया होता है काम

एक जीवाश्म विज्ञानी जीवाश्मों अर्थात प्राचीन जीवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं ताकि पृथ्वी या प्रागैतिहासिक जीवन पर पिछले जीवन की पड़ताल की जा सके। यह छोटे बैक्टिरिया से लेकर विशालकाय डायनासोर तक हैं, ये जीवाश्म एक अरब वर्ष पुराने भी हो सकते हैं। वे प्रागैतिहासिक जीवन रूपों और जीवाश्मों की परीक्षा के माध्यम से पौधे और पशु जीवन के विकास पर शोध करते हैं। वे विलुप्त प्रजातियों के बारे में जानने के लिए जानवरों की हड्डियों, गोले और कास्ट का उपयोग



वर्तमान समय में, छात्रों के लिए संभावनाओं का एक खुला आसमान है, जहां पर वह विचरण करके एक सुखद व सफल भविष्य बना सकते हैं। ऐसा ही एक क्षेत्र है लेक्सोग्राफी। हो सकता है कि आपके लिए यह शब्द नया हो, लेकिन हम आपको बता दें कि शब्दकोश प्रारूप में 'शब्द' लिखने की कला को लेक्सोग्राफी कहते हैं। लैंग्वेज स्टडी के इतिहास में इसका एक अहम स्थान है। जिसमें शब्दकोश निर्माण के दौरान इतिहास, थ्योरी, मैथडोलॉजी और टाइपोलॉजी शामिल है। अगर आप भी अलग-अलग भाषाओं के साथ अपना भविष्य देखते हैं तो आप लेक्सोग्राफी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस क्षेत्र में कैसे बनाएं अपना करियर-

### वया होता है काम

लेक्सोग्राफर एक प्रोफेशनल भाषाविद होते हैं, जो डिक्शनरी, एनसाइक्लोपीडिया व अन्य रेफरेंस टेक्स्ट जैसे लॉ और मेडिकल डिक्शनरी बनाने के लिए रिसर्च, लेखन, संकलन व संपादन करते हैं। आमतौर पर, लेक्सोग्राफी को दो शाखाओं में

# जीवाश्म विज्ञानी के रूप में तलाशें रोजगार की संभावनाएं

करते हैं। साथ ही वह जीवाश्मों का पता लगाने और जीवाश्मों के बारे में प्रासंगिक तथ्यों की पहचान करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। उनके कार्यक्षेत्र में जीवाश्मों का पता लगाना और उनकी खुदाई करना, निष्कर्षों की पहचान, अनुसंधान और उन्हें साझाकरण करना शामिल है।

### पर्सनल स्किल्स

पैलियोन्टोलॉजिस्ट को कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और सांख्यिकीय विश्लेषण में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा उसमें मौखिक और लिखित संचार कौशल भी होने चाहिए, क्योंकि उन्हें पेशेवरों की एक टीम के साथ काम करना होता है। पैलियोन्टोलॉजिस्ट के पास उच्च जिज्ञासा स्तर और इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए। उन्हें तार्किक और गंभीर रूप से सोचने में सक्षम होना चाहिए, जिज्ञासा और अत्यंत विश्लेषणात्मक होना चाहिए, और एक्टिव डेटा या जानकारी से निष्कर्ष निकालने की क्षमता भी इस क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है। चूंकि जीवाश्म विज्ञान एक कठिन काम है, जिसमें जीवाश्मों को खोजने और खुदाई करने के लिए बहुत से बाहरी काम करने की आवश्यकता होती है, एक ड्यूटि क व्यक्ति को धैर्यपूर्ण होना चाहिए।

### योग्यता

पैलियोन्टोलॉजी एक विज्ञान से संबंधित लेकिन व्यापक क्षेत्र है। इसलिए एक जीवाश्म विज्ञानी को भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और

भूविज्ञान को जानना आवश्यक है। जीवाश्म विज्ञान में अधिकांश प्रवेश स्तर के पदों के लिए भूविज्ञान या पृथ्वी विज्ञान में मास्टर डिग्री की आवश्यकता होती है। वहीं रिसर्च और कॉलेज टीचिंग के लिए पीएचडी होना आवश्यक है। कई भाषाओं का ज्ञान इस क्षेत्र के लिए एक अतिरिक्त लाभ है।

### रोजगार की संभावनाएं

एक पैलियोन्टोलॉजिस्ट को कंप्यूटर की अच्छी और विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थान, संग्रहालयों, या राज्य और संघीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों, प्रयोगशालाओं आदि में काम कर सकते हैं। जीवाश्म विज्ञानी सार्वजनिक व निजी दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं तलाश सकते हैं।

### आमदनी

एक जीवाश्म विज्ञानी की आमदनी उनके शिक्षा के स्तर, अनुभव व जहां पर वे काम करते हैं, उस पर निर्भर करती है। निजी क्षेत्र में आपकी योग्यता व अनुभव के आधार पर अच्छा वेतन मिलता है। शुरुआती रूप में एक जीवाश्म विज्ञानी 15000 से 25000 रूपए प्रतिमाह आसानी से कमा सकता है। इसके बाद आपके अनुभव के आधार पर आमदनी बढ़ती जाती है।

### प्रमुख संस्थान

भारत में केवल एक संस्थान जीवाश्म विज्ञान में एक पाठ्यक्रम प्रदान करता है और हैदराबाद के बंडेलागुडा में स्थित जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है।

**एक लेक्सोग्राफर को संबंधित भाषा का गहरा ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी पर उनकी एकड़ी काफी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही विभिन्न भाषाओं को जानने की जिज्ञासा, पढ़ने की आदत, अनुसंधान और विश्लेषणात्मक कौशल, टीम वर्क और लिखित संचार कौशल, प्रभावी समय प्रबंधन और संगठनात्मक कौशल हैं।**

पब्लिशिंग हाउस के लिए काम करते हैं। वह अपना करियर असिसटेंट एडिटर या फिर जूनियर एडिटोरियल असिसटेंट के तौर पर शुरू कर सकते हैं। कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद आप बतौर लेक्सोग्राफर काम कर सकते हैं। आमदनी - यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें लोग सैलरी के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए काम करते हैं। एक पब्लिशिंग हाउस में काम करने वाले लेक्सोग्राफर 15000 से 20000 रूपए प्रतिमाह कमा सकते हैं। वैसे कई लेक्सोग्राफर एक फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं और इस तरह वह हर प्रोजेक्ट के लिए चार्ज करते हैं।

### प्रमुख संस्थान

- डेक्कन संस्थान, पुणे
- पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला
- मद्रास विश्वविद्यालय केरल विश्वविद्यालय, केरल
- भारथिअर यूनिवर्सिटी, कोयंबटूर



# डॉक्टर बनने के लिए जरूरी है नीट परीक्षा ऐसे करें तैयारी

नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट! यह परीक्षा देशभर में मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए आयोजित की जाती है। 12वीं के बाद अगर आप भी डॉक्टर बनना चाहते हैं और इससे संबंधित एमबीबीएस अथवा बीडीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप को इस नीट का एग्जाम देना ही पड़ेगा। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीई द्वारा इसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। इस परीक्षा की योग्यता की बात करें तो 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबजेक्ट के साथ मिनिमम 50 परसेंट मार्क होना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक की कम से कम 17 वर्ष की उम्र होना चाहिए।

नीट परीक्षा की योग्यता की बात करें तो 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबजेक्ट के साथ मिनिमम 50 परसेंट मार्क होना अनिवार्य है। इसके अलावा आवेदक की कम से कम 17 वर्ष की उम्र होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक की कम से कम 17 वर्ष की उम्र होना चाहिए।

साधारण एग्जामिनेशन नहीं है, इसलिए आप भिन्न एक्सपर्ट्स से मार्गदर्शन लेने में संकोच ना करें। इसमें पिछले वर्ष के टॉपर्स का इंटरव्यू आपको मिल जाएगा, जिसे आपको पढ़ना-सुनना चाहिए। इसी प्रकार से जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय भी आपको काफी लाभ पहुंचा सकती है। किन्तु अंत में आपको रीविजनिंग और बेहतरीन डिसिप्लिन के साथ मॉक टेस्ट पेपर अधिक से अधिक बार सॉल्व करना आपके लिए सबसे मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा स्टेट लेवल पर भी इसकी काउंसिलिंग कंडक्ट की जाती है। इसमें अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से सीटों को आवंटित किया जाता है। एनटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी दूसरी कई जानकारीयां आपको मिल जाएगी। यहां तक कि आप मॉक टेस्ट का पेपर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उस हिसाब से अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। करियर एक्सपर्ट्स तैयारी के लिए सलाह देते हैं कि आपको काफी पहले से इस पर ध्यान देना होता है, किन्तु जिस स्तर का टफ एग्जामिनेशन होता है, उसे देखते हुए आपको अंतिम के तकरीबन 2 महीने बेहद सटीकता से रिवीजन पर बिताना होगा। इसके लिए आपको न केवल स्ट्रेंस से बचना होगा, बल्कि बेहतरीन तैयारी के लिए पूरी शेड्यूलिंग करके अलग-अलग सबजेक्ट पर ध्यान देना होगा। ध्यान रहे! यह कोई





**विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान सीएम सुक्खू ने कहा, राज्य में कोई आर्थिक संकट नहीं**

शिमला (एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि राज्य में कोई आर्थिक संकट नहीं है और सरकार 2032 तक सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ देगी। उन्होंने कहा कि सरकार उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम टाकूर द्वारा प्रदेश की वित्तीय स्थिति को कमजोर बनाने के दावे को सीएम सुक्खू ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं की गई है, बल्कि इस केवल छह महीने के लिए स्थगित किया है। साथ ही उन्होंने जयराम टाकूर पर गलत आंकड़े प्रस्तुत करने का आरोप लगाकर कहा कि यदि सही आंकड़े दिखाते, तब स्थिति को लेकर भ्रम नहीं फैलता। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यदि पिछले सरकार के फैसलों का विरोध नहीं कर रहा और कोई नहीं जा रहा, तो उसका मतलब है कि वे भी वास्तविक स्थिति को समझते हैं। इसके अलावा, उन्होंने सोलन और कुल्लू जिलों के अस्पतालों में रोगीों के सर्जरी शुरू करने की योजना की जानकारी दी, जिसके लिए लगभग 28 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक मशीनें खरीदी जाएगी। अंत में सुक्खू ने सवाल उठाया कि कौन सी सरकार बेहतर – वह जो 17 हजार करोड़ की आरंभिकी से चल रही है या वह जिसने 76 हजार करोड़ के कर्ज का दुरुपयोग किया।

**वजन घटाने वाली दवा को लेकर सतर्क ड्रग्स कंट्रोलर... दवा की बिना अनुमति बिक्री और प्रचार पर सख्त**

नई दिल्ली (एजेंसी)। वजन घटाने वाली दवा (जीएलपी-1) की सप्लाई चैन में नैतिक फार्मास्यूटिकल तरीकों को सुनिश्चित करने भारत के ड्रग्स कंट्रोलर ने दवा की बिना अनुमति बिक्री और प्रचार के खिलाफ जांच तेज कर दी है। भारतीय बाजार में जीएलपी-1 आधारित वजन घटाने वाली दवाओं के कई नैतिक वैरिएंट के आने के साथ रिटेल फार्मासियों, ऑनलाइन, थोक विक्रेताओं और वेबनेस वेलीकॉर्पो के माध्यम से इसकी मांग को बढ़ाते चिंता सामने आई है। जब इन दवाओं का उपयोग उचित चिकित्सकीय देखरेख के बिना किया जाता है, तब इनके गंभीर दुष्प्रभाव और संबंधित स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। स्थिति का संज्ञान लेकर भारत के ड्रग्स कंट्रोलर ने राज्य रेगुलेटर्स के सहयोग से फार्मास्यूटिकल सप्लाई चैन में संभावित गलत तरीकों को रोकने और बिना अनुमति बिक्री तथा उपयोग को रोकने के लिए कई लक्षित कार्रवाइयां शुरू की हैं। 10 मार्च 2026 को सभी निर्माताओं को विस्तृत एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से सरग्रेट बिक्री (अप्रत्यक्ष बिक्री) और किसी भी प्रकार के अप्रत्यक्ष प्रचार पर रोक लगाई गई थी, जो उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है। हाल के हप्तों में प्रवर्तन विधियों को काफी बढ़ाया गया है। 49 संस्थाओं पर ऑडिट और निरीक्षण किए गए, जिसमें शामिल हैं ऑनलाइन फार्मासी के गोदाम, दवा के थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, और वेबनेस तथा रिटेलिंग वलीकॉर्पो प्रमुख हैं। ये निरीक्षण देश भर के कई क्षेत्रों में किए गए और इनका मूल्यांकन बिना अनुमति बिक्री, गलत प्रिस्क्रिप्शन (दवा लिखने) के तरीके, और गुमराह करने वाले मार्केटिंग से संबंधित उल्लंघनों की पहचान करना था। रेगुलेटर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि है। चिकित्सकीय देखरेख के बिना वजन घटाने वाली दवाओं का गलत उपयोग गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं का कारण बन सकता है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे ऐसी दवाओं का उपयोग केवल योग्य चिकित्सकों के मार्गदर्शन में ही करें।

**देश के कई राज्यों में गुजरते मार्च में होगी बारिश और बर्फबारी**

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के पहाड़ी राज्यों में बारिश-बर्फबारी और मैदानी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश का असर है। राजस्थान में एक हफ्ते से बारिश और तेज हवा का अनुमान है। जो मार्च के अंत तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 से 31 मार्च के बीच राज्य में दो अलग-अलग ?वेदर सिस्टम सक्रिय होने वाले हैं। मध्यप्रदेश में साइबेरियन सर्कुलेशन सिस्टम का असर है। इसके कारण राज्य के उज्जैन, सागर, ग्वालियर-चंबल संभाग में बादल छाए। इसके कारण दिन के तापमान में गिरावट आई। 26-27 मार्च से आंधी-बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ सहित 10 जिलों में बारिश हुई। यहां तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 मार्च से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा। इससे 3-4 दिन तक पूरे प्रदेश में फिर बारिश हो सकती है। 25 मार्च को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली चिपकने की आशंका है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और सिक्किम में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 26 मार्च को मध्य भारत, बिहार, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान में अंतिले साहज शुरू हुआ आंधी-बारिश का दौर मार्च के अंत तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य में 26 से 31 मार्च के बीच दो अलग-अलग ?वेदर सिस्टम के सक्रिय होने की संभावना जाहिर की है। पिछले 24 घंटे में जयपुर, हनुमानगढ़, झुझुंजी जिलों में बारिश हुई। दोपहर में कोटा, बांरा, अजमेर में बारिश हुई।

**लालू को फिर झटका, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका में कोई डम नहीं... ये कहकर खारिज की**

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली में स्थित दिल्ली हाई कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को लै-ऑफर-जॉब्स मामले में बड़ा झटका देकर उनकी याचिका खारिज कर दी। याचिका में उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उन्हें एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने साफ कहा कि याचिका में कोई डम नहीं है। इस फैसले से लालू यादव को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है और उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सुनवाई के दौरान लालू यादव के वकील ने दलील दी कि यह जांच फ़ौज-कानूनी और दुर्भावनापूर्ण है और उनके मुक्ति के निष्पक्ष जांच के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए का हवाला देकर कहा कि बिना पूर्व मंजूरी के शुरू की गई जांच अवैध मानी जानी चाहिए। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान रेलवे में युपे-डी की नौकरियां देने के बदले लोगों से जमीन ली गई।

**कपिल सिब्बल को फटकराते हुए सुप्रीम कोर्ट... कर्वल 'ईडी,ईडी,ईडी' की रट मत लगाइये**

**सिब्बल से पूछ... क्या किसी सरकारी अधिकारी के मौलिक अधिकार नहीं होते**

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच चल रहे विवाद में महत्वपूर्ण सवाल उठकर पूछे हैं कि क्या किसी सरकारी अधिकारी के मौलिक अधिकार नहीं होते हैं या केवल सरकारी अधिकारी होने के कारण वे अपने मौलिक अधिकार खो देते हैं? जस्टिस पी.के.मिश्रा और जस्टिस एन.वी.अंजारिया की पीठ ने कहा कि ईडी के कुछ अधिकारियों ने मामले में व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर की है। इसके बाद यह तर्क देना कि प्रवर्तन निदेशालय अनुच्छेद 32 के तहत याचिका नहीं दायर कर सकती। यह याचिका ममता बनर्जी पर राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के खिलाफ की गई तलाशी अभियानों में कथित हस्तक्षेप के आरोप में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दो टुक कहा, 'क्या ईडी के अधिकारी हो जाने की वजह से देश के नागरिक नहीं रह जाते?

उन्के मौलिक अधिकारों का क्या?'- पीठ ने कहा कि ईडी के कुछ अधिकारियों ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अदालत में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने चेतावनी कि केवल ईडी,ईडी,ईडी-कहकर मामले को नहीं देखा जा सकता, बल्कि उन अधिकारियों के अधिकारों पर ध्यान देना जरूरी है जो इस पूरे घटनाक्रम में कथित रूप से प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस मिश्रा ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी कर कहा, कृपया ईडी के उन अधिकारियों के मौलिक अधिकारों पर ध्यान दें, जिनके संबंध में अपराध किया गया है। अन्यथा, आप मुख्य मुद्दे से भटक जाएंगे। आप उस दूसरी याचिका को नहीं भूल सकते, जिस याचिका को उन व्यक्तिगत अधिकारियों ने दायर किया है, जो इस अपराध के पीड़ित हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। सिर्फ ईडी, ईडी, ईडी की रट न लगाए। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ



वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जांच करना कोई मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक वैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर जांच में बाधा आती है, तब उसका समाधान कानून के तहत है, न कि अनुच्छेद 32 के जरिए होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसी कानून की व्याख्या किसी विशेष परिस्थिति के संदर्भ में करते, आपराधिक कानून की मूल विशेषताओं के विपरीत जाकर मुसीबतों का नहीं

खोल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी समय का हवाला देकर सुनवाई टालने की मांग भी खारिज की। जस्टिस मिश्रा ने कहा, 'हम न चुनाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, न किसी अपराध का। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह टिप्पणी इस बात का संकेत है कि कोर्ट इस मामले को गंभीरता से देख रहा है और टालने के पक्ष में नहीं है।

**पूरा मामला क्या है?**

यह विवाद जनवरी में तब शुरू हुआ, जब ईडी ने पॉलिटेक्निक कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के वैधानिक अधिकार है। आरोप है कि तब सीएम ममता बनर्जी मौके पर पहुंचीं थी और उन्होंने कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वहां से हटा लिए थे। ईडी का दावा है कि इससे उनकी जांच प्रभावित हुई। यह जांच कथित कोयला तस्करी मामले से जुड़ी है, जिसमें कारोबारी अनूप माजी पर आरोप हैं।

**कश्मीर की अलगाववादी नेता आसिया अंदाबी को उम्रकैद की सजा**

**-दो सहयोगियों को भी 30-30 साल की जेल**

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की कड़कड़गढ़मा अदालत ने कश्मीर की अलगाववादी नेता आसिया अंदाबी को दो सहयोगियों सोफी फरमोदा और नाहिदा

नसरीन को 30-30 साल की जेल की सजा दी गई। तीनों को इससे पहले जनवरी में गैरकानूनी गतिविधियों (निवारण) अधिनियम (यूपीए) के तहत दोषी ठहराया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्र जीत सिंह की अदालत ने सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने अपने पूर्व निर्णय में कहा था कि आसिया अंदाबी और उसकी सहयोगियों ने कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश रची और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल

रहीं। 14 जनवरी को अदालत ने तीनों आरोपियों को यूपीए की विभिन्न धाराओं-धारा 20 (आतंकवादी संगठन का सदस्य होना), धारा 38 (आतंकवादी संगठन से जुड़ना) और धारा 39 (आतंकवादी संगठन का समर्थन) के तहत दोषी ठहराया था। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 153बी, 120बी, 505 और 121ए के तहत भी इन्हें अपराधी पाया गया। इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से वरिष्ठ सरकारी वकील ने कड़ी सजा की मांग की थी। एजेंसी का कहना था कि आरोपी देश के खिलाफ गंभीर साजिशें और गतिविधियों में शामिल रही हैं, इसलिए उन्हें ऐसी सजा दी जानी चाहिए जो समाज में एक कड़ा संदेश दे और भविष्य में इस तरह के अपराधों पर रोक लगे। मौलतबव है कि तीनों आरोपियों को जुलाई 2018 में गिरफ्तार किया गया था। लंबे समय तक चली सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया, जिसे देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ एक सख्त कानूनी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

**राहुल गांधी एक अबोध बालक, वे एक नासमझ बच्चे की तरह हैं**

**-गिरिराज ने विपक्ष के नेता पर कसा तंज, बोले- मोदी के नेतृत्व पर सबको भरोसा**

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अबोध बालक बताया और उन पर कोविड-19 महामारी के दौरान भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। गिरिराज ने कहा कि राहुल गांधी एक अबोध बालक हैं, वे एक नासमझ बच्चे की तरह हैं। मैंने जिन्न किया था कि कोविड काल में भी उनकी गतिविधियां देश में भ्रम फैलाने और लोगों को भड़काने से जुड़ी थीं। आज भारत के नेतृत्व और जनता को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है।



मतलब ही यही है। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि भारत को किसी भी चीज से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भारत की जनता में अपार आत्मविश्वास है। हम किसी भी आपदा में अवसर में बदल सकते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना कर सकते हैं। इस देश की

एकमात्र समस्या विपक्ष का नेता (एलओपी) है। गिरिराज यह टिप्पणी विपक्षी नेता राहुल गांधी द्वारा पश्चिम एशिया की स्थिति के संबंध में अवसर में बदल सकते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना कर सकते हैं। इस देश की एकमात्र समस्या विपक्ष का नेता (एलओपी) है। गिरिराज यह टिप्पणी विपक्षी नेता राहुल गांधी द्वारा पश्चिम एशिया की स्थिति के संबंध में अवसर में बदल सकते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना कर सकते हैं। इस देश की एकमात्र समस्या विपक्ष का नेता (एलओपी) है। गिरिराज यह टिप्पणी विपक्षी नेता राहुल गांधी द्वारा पश्चिम एशिया की स्थिति के संबंध में अवसर में बदल सकते हैं और चुनौतियों का डटकर सामना कर सकते हैं। इस देश की

**मोदी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक पहुंच चुकी है, उनका साम्राज्य जाने वाला है**

**केजरीवाल बोले- आज चुनाव बेईमानी से जीते जा रहे, सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ**

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर 2026 तक नहीं कर पाएंगे। मेरा दिल और राजनीतिक समझ कहती है कि मोदी और अमित शाह जाने वाले हैं। केजरीवाल ने कहा कि मोदी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक पहुंच चुकी है। उनका साम्राज्य जाने वाला है। केजरीवाल ने यह बात शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राजत की किताब 'लॉन्गिन के मौके पर दिल्ली' में कहा। इस



जेल से लौटकर आया तो 1 लाख 6 हजार वोट बचे थे। 42 हजार वोट इन्होंने पीछे से कटवा दिए। उन्होंने कहा कि ये इसी तरह से जीते रहे हैं। वोट जोड़ते हैं, डिलीट करवाते हैं और फर्जी वोट डलवाते हैं। जब देश को इन दोनों से मुक्ति मिलेगी तो एक संतुष्टि यह होगी कि इस लड़ाई में हमने भी योगदान दिया और हम भी जेल गए थे।

अब इतने मीम बन रहे हैं कि किस-किस को जेल में डालेंगे। सोशल मीडिया का पूरा माहौल और इको-सिस्टम है कि बोदो की हत्या बताता है कि मोदी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक पहुंच चुकी है।

बोजीपी के चुनाव जीतने पर केजरीवाल ने कहा कि चुनाव बेईमानी से जीते जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैं नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ा। मेरे जेल जाने से पहले मेरे विधानसभा में जब मैं पिछली बार लड़ा था तो 1 लाख 48 हजार वोट थे। जब मैं

एक्स पर पोस्ट कर मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से पैदा हालात को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शेर बाजार में गिरावट है, एलपीजी की कमी से कई कारोबार प्रभावित हुए हैं और लोग गर्मी में सिलेंडर के लिए कतारों में खड़े हैं। साथ ही प्रवासी मजदूरों के सामने रोजगार का संकट है और रुपया भी निचले स्तर पर पहुंच गया है। जब दुनिया को पहले से अदेशा था, तो सरकार ने पहले से तैयारी क्यों नहीं की और हर संकट का बड़ा आम लोगों पर ही क्यों डाला जाता है।

**अलवर: घीलोड औद्योगिक क्षेत्र की एसी फैक्ट्री में भीषण आग, करोड़ों का हुआ नुकसान**

अलवर (एजेंसी)। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित नीमराणा के घीलोड औद्योगिक क्षेत्र से एक हदयविदारक घटना सामने आई है। यहाँ स्थित ट्रांस एचसीआर नामक एयर कंडीशनर (एसी) बनाने वाली कंपनी में मंगलवार तड़के करीब 3 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी आगोश में ले लिया। रात के सत्रांते में उठती आग की गगनचुंबी लपटें और काले धुएँ का गुबार कई किलोमीटर दूर से साफ देखा जा सकता था, जिससे आसपास के ग्रामीणों और अन्य औद्योगिक इकाइयों में भारी दहशत फैल गई।



घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गया। नीमराणा, बहरोड, घीलोड और सोतानाला से दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर भेजी गईं। दमकल कार्रमियों को आग बुझाने में कड़ी मशकत का सामना करना पड़ा क्योंकि फैक्ट्री के भीतर एसी निर्माण में प्रयुक्त होने वाला ज्वलनशील सामान, प्लास्टिक पार्ट्स, पैकिंग सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का भारी भंडार था। इस सामग्री ने ईंधन का काम किया, जिससे आग तेजी से फैलती चली गई। गनीमत यह रही कि हदरसा देर रात हुआ जब फैक्ट्री में श्रमिक मौजूद नहीं थे, जिसके कारण एक बड़ा जानी नुकसान टल गया।

मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आग की लपटें इतनी तीव्र थीं कि फैक्ट्री की छत धक्क उठी और परिसर के भीतर से रुक-रुक कर धमाकों की आवाजें सुनाई देती रहीं। आशंका जताई जा रही है कि फैक्ट्री के अंदर रखे गैस सिलेंडर, कंप्रेसर या केमिकल कंटेनर अत्यधिक गर्मी के कारण फट गए, जिसने आग को और अधिक विकराल बना दिया। हालांकि, आग लगने के सटीक कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, इस अग्निकांड में करोड़ों रुपये का कच्चा माल और कीमती मशीन जलकर राख हो गई है, जिससे कंपनी को भारी आर्थिक क्षति पहुंची है।

**ईरान की रणनीति देख भारत ने भी पिनाका रॉकेट लॉन्चर रेजिमेंट को ऑपरेशनल किया**

**-इस 'देसी ब्रह्मास्त्र' में है कम समय में भारी तबाही मचाने की क्षमता**

दुर्बो के साथ करीब 2,580 करोड़ रुपये के तबाही मचाने की क्षमता रखता है। यह 122 मिमी रॉकेटों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली और सटीक है। पिनाका 12 रॉकेट एक साथ दाग सकता है और कुछ ही सेकंड में दुश्मन के बड़े इलाके को निशाना बना सकता है। इसकी रेंज 40 से 75 किलोमीटर तक है, जबकि इसके नए गाइड वर्जन 120 किमी तक सटीक हमला करने में सक्षम हैं। आधुनिक युद्ध में छोटे ड्रोन और लो-कॉस्ट मिसाइलें बड़ा खतरा बनकर उभरी हैं। पिनाका का अपग्रेड वर्जन ऐसे लक्ष्यों के खिलाफ भी प्रभावी माना जा रहा है। इसकी एक रॉकेट में 18-24 लॉन्चर होते हैं, जो मिन्टों में सैकड़ों रॉकेट दाग सकते हैं। यह छोटे ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के स्वाम्य अटैक का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। ईरान की तरह दुश्मन अगर सस्ते ड्रोन और



मिसाइलों से हमला करे तो पिनाका का सैल्वो दुश्मन के लॉन्चर और कमांड सेंटर को पहले ही नष्ट कर सकता है। इसका एक रॉकेट महज कुछ लाख रुपये में आ जाता है, जबकि दुश्मन की महंगी मिसाइल को रोकने वाले सिस्टम करोड़ों में होते हैं।

बता दें ईरान-इजरायल संघर्ष ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य के युद्ध पारंपरिक नहीं होंगे, बल्कि टेकनोलॉजी आधारित होंगे, जहां मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट सिस्टम अहम भूमिका निभाएंगे। भारत इसी दिशा में अपनी सेना को तैयार कर रहा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे का मुकाबला किया जा सके। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की रणनीति देखते हुए भारत ने सही समय पर कदम उठाया है।